रोजगार, शिक्षा और विकास का नया संकल्प

छत्तीसगढ़ बनेगा आयुर्वेद और अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र

विज्ञान से विकास की उड़ान: उत्तराखंड के नवाचार युग की शुरुआत

RNI No.: UPHIN/2018/76675
वर्ष 7 | अंक 7 | जुलाई 2026 | ₹20

निर्माणशाला टाइम्स

हिंदी मासिक पत्रिका

विकसित भारत की ओर मजबूत कदम

रोजगार, सुरक्षा और समृद्धि का नया मॉडल



रोजगार से सम्मान तक : PM-VBRY

बदल रहा है भारत के श्रमिकों का भविष्य

युवाओं के सपनों को मिलेगा नया मंच

यमुना एक्सप्रेसवे पर उभर रहा भारत-कोरिया औद्योगिक सहयोग का नया अध्याय

उत्तर प्रदेश में बन रहा अवसरों का शहर

EMPOWERING FARMERS TO REALISE AN ENRICHED FUTURE

KRIBHCO

Cooperative and beyond...



OUR PRODUCTS :

NEEM COATED UREA I BIOFERTILIZERS I CERTIFIED SEEDS I DAP
MOP I NPK I NPS I CITY COMPOST I HYBRID SEED I ZINC SULPHATE

KRIBHCO, world's premier fertilizer producing cooperative has been consistently making sustained efforts towards promoting modern agriculture and cooperatives in the country. It helps farmers maximize their returns through specialised agricultural inputs, rural need based products and other diversified businesses.

OUR SERVICES

KBSK | Krishi Paramarsh Kendra | Farmers Services | Soil Testing | Promotional Programme

KRISHAK BHARATI COOPERATIVE LTD

Registered Office : A-60, Kailash Colony, New Delhi-110048 Phone: 011-29243412
Corporate Office : KRIBHCO BHAWAN, A8-10, Sector -1, Noida-201301, Distt: Gautam Budh Nagar (UP) I **Phones:** 0120-2534631/32/36
Website: www.kribhco.net I **KRIBHCO Kisan Helpline:** 0120-2535628 I **E-mail:** krishipramarsh@kribhco.net

इस अंक में





उत्तर प्रदेश की उड़ान: जेवर से खुले विकास, निवेश और वैश्विक कनेक्टिविटी के नए आसमान





प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना



यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ



विज्ञान से विकास की उड़ान: उत्तराखंड के नवाचार युग की शुरुआत

निर्माणशाला टाइम्स

हिंदी मासिक पत्रिका

मूल्यः 20 रुपये, जुलाई 2026

वर्ष-7 अंकः 7, पृष्ठः 52

प्रधान संपादक
मनोज कुमार सिंह

संपादक
अहमद हसन

सह संपादक
दिव्यांश मिश्रा

Website: www.nirmanshalatimes.com
E-mail: nirmanshalatimes@gmail.com
Mob: +919540284632

ब्यूरो प्रमुख

उत्तराखंड-	**विनय त्रिवाल**
उत्तर प्रदेश-	**लल्लन कुमार मिश्रा**
दिल्ली-	**दिनेश कुमार सिंह**
बिहार-	**सैयद मोहम्मद अली**
हरियाणा-	**संतोष कुमार सिंह**
झारखंड-	**परवेज कमाल**
डिजाइन-	**चंद्रजीत कुमार**

विज्ञापन, प्रसार संपर्क और पत्र व्यवहार
NST MEDIA
WP-02, Block 'C'
Sector - 71, Noida - 201301
Distt. Gautam Buddha Nagar (UP)

कार्यालय

मुद्रक, प्रकाशक एवं स्वामी
सैयद नौशाद मंजर,
मुद्रित- नीलू प्रिंटिंग प्रेस, E-33,
सेक्टर-7, नोएडा, उत्तर प्रदेश से,
प्रकाशित- टी-1,
श्री जी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-5,
नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश से,
संपादक- अहमद हसन।

पत्र का नाम-
निर्माणशाला टाइम्स
(Nirmanshala Times)

RNI NO- UPHIN/2018/76675



संपादकीय

नए भारत का विकास कॉरिडोर

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की परिवर्तनकारी गाथा

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र आज केवल शहरी विस्तार के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि भारत के आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी भविष्य के सशक्त केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। योजनाबद्ध विकास, उत्कृष्ट आधारभूत संरचना, निवेश-अनुकूल नीतियां तथा दूरदर्शी नेतृत्व ने इस पूरे क्षेत्र को राष्ट्रीय एवं वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है।

विशेष रूप से जेवर स्थित Jewar International Airport (जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट) इस क्षेत्र की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर सिद्ध होने जा रहा है। यह केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर भारत के लिए एक व्यापक आर्थिक एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। इसके संचालन से व्यापार, पर्यटन, निर्यात, रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अंतर्गत विकसित हो रहे औद्योगिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, डेटा सेंटर पार्क, लॉजिस्टिक हब, फिल्म सिटी और सेमीकंडक्टर उद्योगों के प्रस्तावित निवेश भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। यह क्षेत्र आज "मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" जैसे राष्ट्रीय अभियानों को धरातल पर साकार करने का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टअप, शिक्षा और रियल एस्टेट के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश और विदेश की अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों ने यहां अपने कार्यालय, उत्पादन इकाइयां एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। परिणामस्वरूप यह क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों का प्रमुख केंद्र बन गया है।

वर्तमान समय में जब वैश्विक निवेशक भारत को एक विश्वसनीय विनिर्माण एवं सेवा केंद्र के रूप में देख रहे हैं, तब नोएडा-ग्रेटर नोएडा-यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र उनकी पहली पसंद के रूप में उभर रहा है। उत्कृष्ट सड़क संपर्क, मेट्रो नेटवर्क, फ्रेट कॉरिडोर, मल्टी-मोडल परिवहन सुविधाएं और आधुनिक शहरी नियोजन इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और अधिक सशक्त बना रहे हैं।

साथ ही, यहां विकसित हो रहे शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्मार्ट टाउनशिप और हरित विकास परियोजनाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आर्थिक प्रगति के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो। यही संतुलित विकास किसी भी आधुनिक शहर की वास्तविक पहचान होती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, उद्योग जगत, सामाजिक संस्थाएं और नागरिक समाज मिलकर इस विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करें। पारदर्शिता, नवाचार, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक समावेशन को केंद्र में रखकर यदि आगे बढ़ा जाए तो यह क्षेत्र न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि सम्पूर्ण भारत की आर्थिक शक्ति का प्रमुख आधार बन सकता है।

निस्संदेह, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र भारत के विकास के उस नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां आधुनिक आधारभूत संरचना, वैश्विक निवेश, तकनीकी नवाचार और जनकल्याण एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति का इंजन बनकर विश्व मानचित्र पर भारत की नई पहचान स्थापित करेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, उद्योग जगत, सामाजिक संस्थाएं और नागरिक समाज मिलकर इस विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करें। पारदर्शिता, नवाचार, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक समावेशन को केंद्र में रखकर यदि आगे बढ़ा जाए तो यह क्षेत्र न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि सम्पूर्ण भारत की आर्थिक शक्ति का प्रमुख आधार बन सकता है।



उत्तर प्रदेश की उड़ान

जेवर से खुले विकास, निवेश और वैश्विक कनेक्टिविटी के नए आसमान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना नए भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्तर प्रदेश की प्रगति का प्रतीक

उत्तर प्रदेश ने विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से वाणिज्यिक उड़ानों का शुभारंभ केवल एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत नहीं, बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति, निवेश आकर्षण और वैश्विक पहचान के नए युग का उद्घाटन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस गति से आधारभूत संरचना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जेवर एयरपोर्ट उसकी एक सशक्त मिसाल बनकर उभरा है।



पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला नया प्रवेश द्वार

लखनऊ से पहुंची इंडिगो की पहली वाणिज्यिक उड़ान और बेंगलुरु के लिए रवाना हुई पहली प्रस्थान उड़ान ने क्षेत्र के विकास का नया अध्याय लिख दिया। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के लाखों यात्रियों को विश्वस्तरीय हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा। यह एयरपोर्ट जल्द ही देश के 16 से अधिक प्रमुख शहरों से जुड़कर यात्रियों के लिए यात्रा को और अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक बनाएगा।

वैश्विक कनेक्टिविटी की ओर बढ़ते कदम

फिलहाल घरेलू उड़ानों के संचालन के साथ शुरू हुआ यह एयरपोर्ट निकट भविष्य में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का भी प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।











आधुनिक तकनीक और भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल तकनीकी दृष्टि से ही आधुनिक नहीं है, बल्कि इसकी वास्तुकला में भारतीय संस्कृति और उत्तर प्रदेश की विरासत की झलक भी दिखाई देती है। डिजीयात्रा, सेल्फ चेक-इन, सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों को सहज और स्मार्ट यात्रा अनुभव मिलेगा। वहीं टर्मिनल परिसर में वाराणसी के घाटों और भारतीय स्थापत्य की प्रेरणा इसे सांस्कृतिक पहचान भी प्रदान करती है।

रोजगार, निवेश और उद्योगों को मिलेगा नया बल

एयरपोर्ट के संचालन से प्रदेश में निवेश की संभावनाएं और अधिक मजबूत होंगी। इसके साथ विकसित किया गया आधुनिक कार्गो हब ई-कॉमर्स, निर्यात, कृषि उत्पादों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को नई गति देगा। लाखों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी का उत्कृष्ट उदाहरण

एयरपोर्ट को सड़क, बस, टैक्सी और भविष्य में रेल एवं रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क से जोड़ने की योजना इसे देश के सबसे बेहतर कनेक्टेड एयरपोर्ट्स में शामिल करेगी। यह सुविधा यात्रियों के साथ-साथ उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

'नए उत्तर प्रदेश' की नई पहचान

1.2 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता के साथ शुरू हुआ यह एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यह परियोजना केवल एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आत्मविश्वास, आधुनिक सोच और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण का प्रतीक है। जेवर एयरपोर्ट प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

"जेवर से उड़ान, विकास की नई पहचान — उत्तर प्रदेश बना वैश्विक कनेक्टिविटी का नया केंद्र।"

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत इस बात का प्रमाण है कि जब दूरदर्शी नेतृत्व, मजबूत योजना और प्रभावी क्रियान्वयन एक साथ आते हैं, तो विकास के नए आयाम स्थापित होते हैं। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ■

प्राकृतिक खेती से सशक्त होगा भारत का भविष्य

कानपुर कार्यशाला में किसानों को मिला नवाचार और सम्मान का मंच

स्वस्थ पीढ़ियों और समृद्ध कृषि की ओर बढ़ता कदम





आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए प्राकृतिक खेती आज एक प्रभावी और दूरदर्शी विकल्प बनकर उभर रही है। इसी सोच को साकार करने के उद्देश्य से कानपुर में आयोजित 'प्राकृतिक खेती कार्यशाला-2026' किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार और प्रेरणा का महत्वपूर्ण मंच साबित हुई।

कार्यक्रम में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने, किसानों को आधुनिक तकनीकों एवं वैज्ञानिक तरीकों से जोड़ने तथा टिकाऊ कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया गया।



विशेषज्ञों ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करते हुए पर्यावरण-अनुकूल खेती के लाभों से अवगत कराया।

किसानों को मिला सम्मान, बढ़ा आत्मविश्वास

कार्यशाला का एक महत्वपूर्ण आकर्षण प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कृषकों का सम्मान रहा। यह सम्मान न केवल उनके प्रयासों की सराहना है, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। सम्मानित किसानों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत में कमी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि तथा बेहतर आय के अवसर प्राप्त हुए हैं।

तकनीक और परंपरा का सफल संगम

कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि पारंपरिक कृषि ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डिजिटल तकनीकों, जल संरक्षण,

जैविक संसाधनों के उपयोग और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर किसान

न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

हरित भविष्य की मजबूत नींव

प्राकृतिक खेती केवल एक कृषि पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज, सुरक्षित पर्यावरण और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। कानपुर की यह कार्यशाला इस दिशा में एक सार्थक पहल साबित हुई, जिसने किसानों को नई ऊर्जा, नई सोच और नए अवसर प्रदान किए। ■

पलाश की उड़ान

ग्रामीण महिलाओं की मेहनत से दुनिया के बाजारों तक पहुँचा झारखण्ड का आम



मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के विज़न ने लिखी ग्रामीण समृद्धि की नई कहानी

झारखण्ड आज ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की दूरदर्शी सोच और ग्रामीण महिलाओं की अथक मेहनत ने राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। 'पलाश' ब्रांड के तहत संचालित झारखण्ड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव न केवल किसानों की आय बढ़ा रहा है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई पहचान भी दिला रहा है।

बिरसा हरित ग्राम योजना से बदली लाखों परिवारों की तस्वीर

> "पलाश केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि झारखण्ड की ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास, किसानों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत के सपने का सशक्त प्रतीक है।"

कोरोना काल में शुरू की गई बिरसा हरित ग्राम योजना आज ग्रामीण आजीविका का मजबूत आधार बन चुकी है। राज्य के लगभग 1.86 लाख एकड़ क्षेत्र में विकसित आम के बगीचे करीब 2.15 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए आय का स्थायी स्रोत बने हैं। वर्तमान सीजन में 52 हजार एकड़ क्षेत्र तुड़ाई के लिए तैयार है और लगभग 50 हजार मीट्रिक





टन आम उत्पादन का अनुमान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है।

'पलाश' बना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक

झारखण्ड की सखी मंडल की दीदियाँ आज केवल खेती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कलेक्शन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें नेतृत्व की भूमिका में भी स्थापित कर रही है। किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से जुड़ाव ने उन्हें संगठित बाजार और बेहतर मूल्य उपलब्ध कराया है।

दुबई और लंदन तक पहुँची झारखण्ड की मिठास

झारखण्ड का आम अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है। सिमडेगा से प्रीमियम आमों की खेप लंदन पहुँची है, जबकि रामगढ़ से दुबई को बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया है। यह उपलब्धि न केवल राज्य की कृषि क्षमता को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण किसानों के उत्पादों को वैश्विक मंच तक पहुँचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित करती है।

संगठित मार्केटिंग से किसानों को मिल रहा बेहतर लाभ

ग्रेड-आधारित मार्केटिंग मॉडल के माध्यम से आमों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में व्यवस्थित तरीके से पहुँचाया जा रहा है। 'पलाश'



और 'अपना मार्ट' जैसे प्लेटफॉर्म किसानों और उपभोक्ताओं के बीच भरोसे का पुल बन रहे हैं। गुणवत्ता के आधार पर तैयार की गई विपणन रणनीति किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित कर रही है।

60 लाख से अधिक का कारोबार, बढ़ते अवसरों की दस्तक

राज्य के 115 से अधिक FPOs की सक्रिय भागीदारी से अब तक 2,24,200 किलोग्राम आमों की बिक्री हो चुकी है और 60.51 लाख से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया है। यह केवल एक व्यावसायिक उपलब्धि नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों के आत्मविश्वास की जीत है। ब्लिंकिट, रिलायंस फ्रेश और कशिश मॉल जैसे बड़े कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स से संभावित साझेदारी भविष्य में बाजार विस्तार की नई संभावनाएँ खोल रही है।

ग्रामीण विकास का झारखण्ड मॉडल

'पलाश' ब्रांड के माध्यम से झारखण्ड ने यह साबित कर दिया है कि यदि सरकारी योजनाओं को सही दिशा, मजबूत क्रियान्वयन और समुदाय की भागीदारी मिले, तो ग्रामीण विकास केवल एक सपना नहीं बल्कि वास्तविकता बन सकता है। यह पहल कृषि, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और निर्यात संवर्धन का ऐसा समन्वित मॉडल प्रस्तुत कर रही है, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। ■

रेल विकास की नई रफ्तार
राजस्थान को मिली जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात



भारत के विकसित भविष्य की ओर बढ़ते कदमों को नई गति देते हुए राजस्थान ने रेलवे विकास के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ केवल एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई यह रेल सेवा राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी। इससे लाखों यात्रियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और श्रमिकों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती यात्रा का लाभ मिलेगा।

खाटूश्यामजी भक्तों के लिए विशेष सौगात

रेल मंत्री द्वारा सीकर जिले के सुंदरपुरा में नए रेलवे स्टेशन की घोषणा ने प्रदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत प्रदान की है। खाटूश्यामजी धाम आने वाले भक्तों के लिए यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

खातीपुरा : रेलवे आधुनिकीकरण का नया केंद्र

205 करोड़ रुपये की लागत से विकसित मेगा कोचिंग टर्मिनल खातीपुरा, उत्तर पश्चिम रेलवे की कार्यक्षमता को नई मजबूती देगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह टर्मिनल लगभग 450 रेलगाड़ियों के रखरखाव की क्षमता रखता है। वंदे भारत, डेमू और एलएचबी



रेक सहित विभिन्न ट्रेनों का मेंटेनेंस एक ही स्थान पर होने से परिचालन दक्षता बढ़ेगी तथा यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे क्रांति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल विश्वस्तरीय परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। आधुनिक स्टेशन, नई रेल लाइनें, विद्युतिकरण, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी योजनाएं देश की प्रगति को नई दिशा दे रही हैं।

राजस्थान में रेलवे विकास के लिए वर्ष 2026-27 में 10,228 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है, जो वर्ष 2009-14 की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक है। वर्तमान में प्रदेश में 76,800 करोड़ रुपये से अधिक लागत की रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

नई रेल सेवाएं, आधुनिक टर्मिनल, विस्तारित रेल नेटवर्क और उन्नत यात्री सुविधाएं प्रदेश को विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर कर रही हैं। यह पहल न केवल यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि शिक्षा, पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।

विकास के इंजन बन रहे फ्रेट कॉरिडोर

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं शक्ति कार्गो टर्मिनल योजनाएं राजस्थान को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित कर रही हैं। इससे व्यापार, निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा प्राप्त होगी।



विकसित राजस्थान की ओर मजबूत कदम

नई रेल सेवाएं, आधुनिक टर्मिनल, विस्तारित रेल नेटवर्क और उन्नत यात्री सुविधाएं प्रदेश को विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर कर रही हैं। यह पहल न केवल यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि शिक्षा, पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।

जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ वास्तव में "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" की भावना को सशक्त बनाते हुए विकास, कनेक्टिविटी और जनसुविधा के नए अध्याय का शुभारंभ है। ■

हरियाणा में बागवानी क्रांति का नया अध्याय

किसान समृद्धि और कृषि नवाचार को मिली नई उड़ान



हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए झज्जर जिले के रईया और मुनीमपुर में अत्याधुनिक बागवानी संस्थानों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा लगभग 75 करोड़ रुपये की 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्रदेश के ग्रामीण विकास, कृषि नवाचार और किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रईया अनुसंधान केंद्र बनेगा किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सेतु

करीब 100 एकड़ भूमि पर स्थापित अत्याधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र भविष्य में किसानों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, उन्नत पौध किस्मों के विकास और जलवायु अनुकूल खेती का प्रमुख केंद्र बनेगा। यहां विकसित होने वाली आधुनिक तकनीकें किसानों की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में सहायक होंगी, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भारत-इजरायल सहयोग से आधुनिक कृषि को नई दिशा

मुनीमपुर में स्थापित बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र भारत और इजरायल के सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह केंद्र किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक उत्पादन तकनीक और बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इजरायल की उन्नत कृषि तकनीकों का लाभ हरियाणा के किसानों तक पहुंचाकर कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

फसल विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आय

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा आज देश के अग्रणी बागवानी राज्यों में शामिल है। भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत, सूक्ष्म सिंचाई और किसान उत्पादक संगठनों जैसी योजनाओं ने किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर अधिक लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित किया है। सरकार का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

'सतत बागवानी संवर्धन परियोजना' बनेगी परिवर्तन की आधारशिला

2,738 करोड़ रुपये की लागत से संचालित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 400 बागवानी क्लस्टरों का विकास, 500 उत्पादक समूहों का गठन, 1,000 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और 65 हजार एकड़ क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बेहतर बाजार उपलब्ध होंगे।

युवाओं के लिए कृषि में उद्यमिता के नए अवसर

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि कृषि अब केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्टार्टअप, एग्री-बिजनेस, ड्रोन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ई-कॉमर्स जैसे अनेक अवसरों का क्षेत्र बन चुका है। युवा कृषि को रोजगार मांगने का नहीं, बल्कि रोजगार सृजन का माध्यम बनाएं।

बादली विधानसभा क्षेत्र को मिली विकास परियोजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए आधुनिक अस्पताल, आदर्श खेल स्टेडियम, नई सड़कें, सीवरेज एवं पेयजल परियोजनाएं, फसल खरीद केंद्र और सिंचाई सुविधाओं सहित अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। इन योजनाओं से क्षेत्र की आधारभूत संरचना मजबूत होगी और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते कदम

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि रसायनों पर निर्भरता कम करके सुरक्षित, टिकाऊ और स्वास्थ्यवर्धक कृषि व्यवस्था विकसित की जा सकती है। यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण और समृद्ध कृषि का आधार बनेगी। ■

पहाड़ की बेटी ने रची सफलता की नई इबारत

ऐपन कला से आत्मनिर्भरता तक

मानसी कापड़ी बनीं युवा उद्यमिता की प्रेरक मिसाल

उत्तराखण्ड की युवा शक्ति आज नवाचार, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी परिवर्तनकारी यात्रा का एक प्रेरणादायक उदाहरण हैं पिथौरागढ़ की मानसी कापड़ी, जिन्होंने अपनी पारंपरिक कला को केवल शौक तक सीमित न रखते हुए उसे एक सफल व्यवसायिक पहचान प्रदान की है। लक्ष्मण सिंह महार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ की बीबीए छात्रा मानसी बचपन से ही उत्तराखण्ड की प्रसिद्ध ऐपन कला में विशेष रुचि रखती थीं। उनकी रचनात्मकता और कलात्मक कौशल को नई दिशा तब मिली जब उन्होंने वर्ष 2024 में देवभूमि उद्यमिता योजना (DUY) के बूटकैंप में भाग लिया। इस कार्यक्रम ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि स्थानीय कला, परंपरा और प्रतिभा को उद्यमिता के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में कैसे बदला जा सकता है।

बूटकैंप के दौरान मानसी ने अपने ऐपन आधारित व्यवसायिक विचार को प्रस्तुत किया। उनकी स्पष्ट सोच, नवाचारी दृष्टिकोण और व्यवसायिक समझ ने निर्णायकों को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप उनका चयन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के लिए हुआ। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, व्यवसाय संचालन और बाजार विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त की।

प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर मानसी ने अपना उद्यम "Homies Vibes" प्रारम्भ किया, जो आज पारंपरिक ऐपन कला को आधुनिक बाजार से जोड़ने का सफल माध्यम बन चुका है। फरवरी 2025 में आयोजित देवभूमि उद्यमिता स्टार्टअप मेगा इवेंट में उनके उद्यम को 75,000 का सीड फंड प्राप्त हुआ, जिसने उनके व्यवसाय को नई गति प्रदान की।

आज मानसी प्रतिवर्ष लगभग 80,000 मूल्य के उत्पादों की बिक्री कर रही हैं और निरंतर अपने ग्राहक आधार का विस्तार कर रही हैं। उनकी सफलता यह सिद्ध करती है कि यदि युवाओं को सही प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध हों, तो वे स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आत्मनिर्भरता की नई कहानियाँ लिख सकते हैं।

मानसी कापड़ी की यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड की उन हजारों युवतियों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने का साहस रखती हैं। उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि प्रतिभा जब अवसर से मिलती है, तब सफलता की नई इबारत लिखी जाती है।

जब परंपरा नवाचार से जुड़ती है, तब केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का निर्माण होता है। मानसी कापड़ी की सफलता इसी सकारात्मक परिवर्तन की कहानी है।"



देवभूमि उद्यमिता योजना : युवाओं के सपनों को दे रही नई उड़ान

उत्तराखण्ड सरकार की महत्वाकांक्षी देवभूमि उद्यमिता योजना राज्य के युवाओं को रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में संचालित यह योजना विद्यार्थियों को उद्यमिता प्रशिक्षण, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, बाजार संपर्क, ब्रांडिंग सहायता और सीड फंडिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर नवाचार आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित कर रही है। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय कला, संस्कृति और संसाधनों पर आधारित उद्यमों को बढ़ावा देकर यह योजना आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मानसी कापड़ी जैसी सफलता की कहानियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि देवभूमि उद्यमिता योजना केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। ■

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

रोजगार से सामाजिक सुरक्षा तक का सशक्त सेतु



उ रत आज केवल रोजगार सृजन की दिशा में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की ओर भी तेज़ी से अग्रसर है। इसी सोच को साकार करने वाली **प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)** देश के श्रमिकों, युवाओं और उद्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है।

लगभग एक वर्ष के भीतर ही इस योजना ने रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगभग 99,446 करोड़ के प्रावधान वाली यह योजना दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य लेकर चल रही है। इनमें बड़ी संख्या उन युवाओं की है जो पहली बार औपचारिक रोजगार क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।

भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह रही है कि देश का विशाल श्रमिक वर्ग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। ऐसे लाखों श्रमिक वर्षों तक काम करने के बावजूद भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से वंचित रहते हैं। PM-VBRY इस स्थिति को बदलने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

इस योजना के माध्यम से पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), पेंशन और संगठित रोजगार का लाभ प्रारंभिक अवस्था से ही मिलने लगता है। इससे उनका आर्थिक भविष्य अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ बनता है। उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि लाखों युवा पहले ही इस योजना के माध्यम से औपचारिक रोजगार से जुड़ चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग की है। महिला सहभागिता में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब प्रत्येक नागरिक को केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और सुरक्षित भविष्य भी प्राप्त हो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी पहल है।

योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष नियोक्ताओं को दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए निर्धारित अवधि तक आर्थिक सहायता प्रदान करके सरकार उद्योगों को अधिक से अधिक औपचारिक नियुक्तियाँ करने के लिए प्रेरित कर रही है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को इससे बड़ा लाभ मिल रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद ये उद्यम अब अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।

यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रमिक कल्याण, उद्यम विकास और सामाजिक सुरक्षा—इन तीनों उद्देश्यों का सफल समन्वय प्रस्तुत करती है। इससे श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन, उद्यमों को प्रशिक्षित एवं स्थायी कार्यबल तथा राष्ट्र को मजबूत आर्थिक आधार प्राप्त होता है।

आज आवश्यकता है कि श्रमिक संगठन, उद्योग जगत, सामाजिक संस्थाएँ और सरकार मिलकर इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाएँ, ताकि प्रत्येक पात्र युवा और श्रमिक इसका लाभ प्राप्त कर सके। यदि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन निरंतर जारी रहा तो यह भारत के सामाजिक सुरक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। ■

डिजिटल भारत से विकसित भारत की ओर

12 वर्षों में विश्व को दिशा देता भारत



आधुनिक भारत की तीन ऐतिहासिक उपलब्धियाँ

पिछले 12 वर्षों में भारत ने तकनीक, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिन्हें आज पूरी दुनिया अध्ययन और अनुकरण के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल क्रांति को जन-जन तक पहुँचाकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया है।

1. आधार : दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली

भारत का आधार आज विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बन चुका है। 140 करोड़ से अधिक भारतीयों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान कर सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है।

सकारात्मक प्रभाव:

- सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुँचा।
- फर्जी लाभार्थियों पर प्रभावी रोक लगी।
- बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित हुई।
- डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत आधार मिला।

2. यूपीआई : विश्व का सबसे बड़ा रियल-टाइम भुगतान नेटवर्क

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत को नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेज़ी से अग्रसर किया है। आज सड़क के रेहड़ी वाले से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक, हर जगह यूपीआई भुगतान सामान्य बात बन चुका है।

'एक क्लिक में लेन-देन, डिजिटल भारत की पहचान"'

सकारात्मक प्रभाव:

- कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।
- छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उद्यमियों को नई शक्ति।
- सुरक्षित, तेज़ और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था।
- भारत का डिजिटल भुगतान मॉडल कई देशों के लिए प्रेरणा बना।

'डिजिटल नवाचार, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास के संगम ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। आधार ने पहचान दी, यूपीआई ने सशक्त बनाया और आयुष्मान भारत ने सुरक्षा प्रदान की। यही है विकसित भारत की मजबूत नींव।'

3. आयुष्मान भारत : स्वास्थ्य सुरक्षा का विश्व का सबसे बड़ा कवच

Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो करोड़ों गरीब और वंचित परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है।

"स्वस्थ नागरिक, सशक्त राष्ट्र"

सकारात्मक प्रभाव:

- गरीब परिवारों को महंगे इलाज से आर्थिक सुरक्षा।
- लाखों लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच।
- ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक समानता को बल।

विश्वगुरु भारत की नई पहचान

आधार, यूपीआई और आयुष्मान भारत केवल योजनाएँ नहीं हैं, बल्कि **नए भारत के परिवर्तनकारी स्तंभ** हैं। इन पहलों ने यह सिद्ध किया है कि जब तकनीक को जनकल्याण से जोड़ा जाता है, तब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है। ■

समग्र स्वास्थ्य की ओर भारत का सशक्त कदम

आयुष से सशक्त हो रहा स्वस्थ भारत



भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य, रोकथाम और जीवनशैली आधारित कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी सोच के अनुरूप आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है।

देशभर के स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में आयुष सेवाओं का समावेश आम नागरिकों को प्राकृतिक, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य विकल्प प्रदान कर रहा है। इससे न केवल लोगों की स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी है, बल्कि रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने को भी प्रोत्साहन मिला है।

'स्वास्थ्य केवल रोगमुक्ति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की अवस्था है — और आयुष इसी समग्र दृष्टि को साकार कर रहा है।'

आयुष मंत्रालय की स्थापना भारत की पारंपरिक चिकित्सा विरासत को नई पहचान देने वाला ऐतिहासिक कदम साबित हुई है। मंत्रालय के नेतृत्व में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और जन-जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां वैश्विक मंच पर भी अपनी प्रभावशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण सम्मान प्राप्त कर रही हैं।

विश्व स्तर पर योग और आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता भारत की सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी समृद्ध विरासत का प्रमाण है। अनेक देशों में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति बढ़ता विश्वास यह दर्शाता है कि समग्र स्वास्थ्य की भारतीय अवधारणा विश्व समुदाय को भी आकर्षित कर रही है।

निर्माणशाला टाइम्स का मानना है कि आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान का संतुलित समन्वय एक स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आयुष आधारित स्वास्थ्य मॉडल न केवल उपचार का विकल्प है, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक सकारात्मक और टिकाऊ जीवनशैली का मार्ग भी है। ■



हरित परिवहन की नई उड़ान

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ



स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ता भारत, भविष्य के परिवहन का नया अध्याय

देश में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के साथ-साथ ग्रीन हाइड्रोजन आधारित बसों का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। एनटीपीसी दादरी द्वारा विकसित **ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट** भारत में हरित परिवहन क्रांति का नया प्रतीक बनकर उभर रहा है।

ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर आधारित ये बसें पारंपरिक डीजल ईंधन के स्थान पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से संचालित होंगी। यह पहल न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी, बल्कि देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में भी आगे बढ़ाएगी।

"आज की ग्रीन हाइड्रोजन बसें, कल के स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेंगी।"

पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा, जिससे भूजल संसाधनों पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। प्रतिदिन लगभग **2080 किलोग्राम ऑक्सीजन** का उत्पादन होगा, जो लगभग **1750 पेड़ लगाने के बराबर पर्यावरणीय** लाभ प्रदान करेगा।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों से उत्सर्जन के रूप में केवल जल निकलेगा, जिससे वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। अनुमान है कि इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग **1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO) उत्सर्जन में कमी होगी।**

भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन

यह परियोजना देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन के रूप में स्थापित की जा रही है। इससे भविष्य में हरित ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन के विस्तार को नई गति मिलेगी और भारत वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अपनी अग्रणी भूमिका मजबूत करेगा।

आधुनिक तकनीक और बेहतर यात्रा अनुभव

42 यात्रियों की क्षमता वाली तथा 12 मीटर लंबी प्रत्येक बस में एक बार में **56 किलोग्राम हाइड्रोजन** भरी जा सकेगी। इस क्षमता के साथ बसें एक बार में लगभग **750 किलोमीटर तक की यात्रा** कर सकेंगी, जो लंबी दूरी के सार्वजनिक परिवहन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

आत्मनिर्भर और हरित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी परियोजना स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ परिवहन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल न केवल प्रदूषण कम करने में सहायक होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन मॉडल का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। ■

हरित परिवहन की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश

जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मिली नई उड़ान







"ग्रीन मोबिलिटी, स्मार्ट कनेक्टिविटी और सतत विकास के नए युग में प्रवेश करता गौतमबुद्धनगर"

उत्तर प्रदेश एक बार फिर आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नई मिसाल स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 45 इलेक्ट्रिक एवं 3 हाइड्रोजन बसों के संचालन का शुभारंभ केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि भविष्य के हरित और सतत विकास का सशक्त संकेत है।

यह पहल क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के साथ-साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और भविष्य में 500 बसों तक विस्तार की योजना प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण आज आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर, स्टार्टअप एवं सेमीकंडक्टर उद्योगों के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था निवेश, रोजगार और शहरी जीवन की गुणवत्ता को नई गति प्रदान करेगी।

विशेष रूप से हाइड्रोजन बसों का संचालन प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करेगा। यह पहल कार्बन उत्सर्जन कम करने, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और नेट-जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, मेट्रो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और स्मार्ट परिवहन नेटवर्क के माध्यम से विकास के नए अध्याय लिख रहा है। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बसों की यह सौगात केवल यात्रा को आसान नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और बेहतर पर्यावरण की नींव भी मजबूत करेगी। ■

स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल क्रांति

e-Sanjeevani

बना करोड़ों भारतीयों का भरोसेमंद डॉक्टर



आज के दौर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच केवल शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसी सोच को साकार करते हुए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल e-Sanjeevani देश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल रही है।

e-Sanjeevani के माध्यम से अब तक 42 करोड़ से अधिक टेली-कंसल्टेशन सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है, जिन्हें अब विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती।

ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में रहने वाले मरीज अब अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या मोबाइल फोन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों से जुड़ सकते हैं। इससे समय, धन और ऊर्जा की बचत होने के साथ-साथ समय पर उपचार भी सुनिश्चित हो रहा है।

e-Sanjeevani ने डिजिटल तकनीक को जनसेवा का सशक्त माध्यम बनाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाया है। यह पहल "सबका स्वास्थ्य, सबका कल्याण" के संकल्प को मजबूत करने के साथ भारत को डिजिटल हेल्थकेयर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है।

निस्संदेह, e-Sanjeevani एक ऐसा उदाहरण है जो साबित करता है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की दूरी को समाप्त किया जा सकता है और हर नागरिक तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा सकती है। ■

युवा शक्ति का डिजिटल महाकुंभ:

MY Bharat Portal पर 2.07 करोड़ से अधिक युवाओं का ऐतिहासिक जुड़ाव



"युवा जुड़े, राष्ट्र बढ़े — MY Bharat के साथ विकसित भारत की ओर एक सशक्त कदम।"

नए भारत के निर्माण में युवाओं की बढ़ती भागीदारी

भारत की युवा शक्ति देश के विकास की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया **MY Bharat (Mera Yuva Bharat) Portal** आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर चुका है। 2.07 करोड़ से अधिक युवा इस मंच पर पंजीकृत हो चुके हैं, जो इसे देश के सबसे बड़े युवा सहभागिता प्लेटफॉर्मों में से एक बनाता है।

युवाओं को मिला अवसरों का एकीकृत मंच

MY Bharat Portal युवाओं को स्वयंसेवा, कौशल विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण और विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों से जोड़ने का कार्य कर रहा है। यह मंच युवाओं को केवल जानकारी ही नहीं देता, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र के लिए सकारात्मक योगदान देने के अवसर भी प्रदान करता है।

डिजिटल भारत की नई पहचान

डिजिटल तकनीक के माध्यम से करोड़ों युवाओं का एक ही मंच पर जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि भारत का युवा वर्ग तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए भी कर रहा है। यह पहल डिजिटल भारत के विजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है।

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की निर्णायक भूमिका

MY Bharat Portal के माध्यम से युवा विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। इससे उनमें नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भाव का विकास हो रहा है। यह मंच युवाओं को "भागीदार" से आगे बढ़ाकर "परिवर्तन का वाहक" बना रहा है। ■

2.07 करोड़ से अधिक युवाओं का MY Bharat Portal से जुड़ना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में युवा शक्ति की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत का युवा वर्ग जागरूक, सक्रिय और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है।



भूमंडलीय व्यापार की ओर उत्तर प्रदेश का सशक्त कदम

UP International Trade Show-2026

वैश्विक निवेश, निर्यात और 'मेक इन यूपी' को नई उड़ान

उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार और निवेश का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए **यू.पी. इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS)-2026** के चतुर्थ संस्करण की तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी **25 से 29 सितम्बर, 2026** तक **इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा** में आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन की तैयारियों की समीक्षा प्रमुख सचिव, एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन **शशि भूषण लाल सुशील** की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में की गई।

बैठक में आयोजन को पहले से अधिक भव्य, सुव्यवस्थित और वैश्विक स्तर का बनाने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, आधारभूत सुविधाओं तथा आगंतुकों के लिए विश्वस्तरीय व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। देश-विदेश से आने वाले खरीदारों, निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और प्रदर्शकों को उत्कृष्ट सुविधाएं



उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल, चिकित्सा एवं आपातकालीन सेवाएं, यातायात प्रबंधन, आवास, ब्रांडिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सुरक्षा सहित विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु अलग-अलग समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा गया। जिला प्रशासन, पुलिस, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और इंडिया एक्सपो मार्ट के बीच प्रभावी समन्वय के साथ नियमित समीक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।

प्रमुख सचिव ने कहा कि **यू.पी. इंटरनेशनल ट्रेड शो** केवल एक व्यापारिक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निर्यात सामर्थ्य, निवेश संभावनाओं और **'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)'** जैसे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रभावशाली मंच है। यह आयोजन प्रदेश के उद्यमियों, एमएसएमई इकाइयों, स्टार्टअप्स और निर्यातकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों, मजबूत औद्योगिक आधार और प्रभावी प्रशासनिक समन्वय के साथ **UPITS-2026** प्रदेश की आर्थिक प्रगति, निवेश आकर्षण और निर्यात संवर्धन की नई इबारत लिखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनने जा रहा है। ■

नारी शक्ति का स्वर्णिम उत्कर्ष

12 वर्षों में सशक्त भारत की नई पहचान



भारत के विकास की कहानी में पिछले 12 वर्षों का दौर महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का एक स्वर्णिम अध्याय बनकर उभरा है। आज देश की करोड़ों महिलाएँ केवल परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और उद्यमिता के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छू रही हैं।

32 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन धन खाते वित्तीय समावेशन की क्रांति का प्रतीक बने हैं, जिससे महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं **10 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** से जुड़कर सामूहिक विकास और स्वरोजगार की नई मिसाल कायम कर रही हैं।

10.5 करोड़ से अधिक उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन ने महिलाओं को धुएँ से मुक्ति दिलाकर उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। साथ ही लगभग **16 करोड़ परिवारों तक नल से जल की सुविधा** पहुँचने से महिलाओं का श्रम और समय दोनों बचे हैं, जिससे वे शिक्षा, रोजगार और अन्य रचनात्मक कार्यों में अधिक योगदान दे पा रही हैं।

देश में **3 करोड़ से अधिक महिला उद्यमियों** का उभरना आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही **3 करोड़ से अधिक 'लखपति दीदियाँ'** ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व, आत्मविश्वास और समृद्धि की प्रेरणादायक कहानी लिख रही हैं।

ये उपलब्धियाँ केवल आँकड़े नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे भारत की तस्वीर हैं जहाँ **नारी शक्ति विकास की सहभागी ही नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता भी बन रही है।** महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सशक्त उपस्थिति देश को एक मजबूत, समावेशी और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है।

"सशक्त नारी, समृद्ध भारत" का यह संकल्प आज करोड़ों महिलाओं की सफलता के रूप में साकार होता दिखाई दे रहा है, जो नए भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी हैं। ■

गो सेवा से समृद्धि की नई राह

उत्तर प्रदेश में मिनी बायोगैस क्रांति का शुभारंभ



"जब गो सेवा बनेगी ऊर्जा और समृद्धि का आधार, तब आत्मनिर्भर गांवों से सशक्त होगा भारत का भविष्य।"

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गो संरक्षण को नई दिशा और नई ऊर्जा मिल रही है। अब गो सेवा केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का विषय नहीं रह गई है, बल्कि इसे ग्रामीण आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक समृद्धि से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के एक लाख ग्रामीण घरों में मिनी बायोगैस प्लांट स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है।

यह पहल गांवों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई मिसाल स्थापित करेगी। 25 से 50 हजार रुपये की लागत से लगने वाले ये मिनी बायोगैस संयंत्र गोबर और जैविक अपशिष्ट से स्वच्छ ईंधन तैयार करेंगे, जिससे ग्रामीण परिवारों की रसोई गैस पर होने वाला खर्च काफी कम होगा। साथ ही इससे प्राप्त होने वाली जैविक स्लरी किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक खाद का कार्य करेगी, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी।

यह योजना गो संरक्षण को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ते हुए किसानों और पशुपालकों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर भी पैदा करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा और रसायनमुक्त कृषि को नई गति प्राप्त होगी।

'गो सेवा से समृद्धि' की यह अवधारणा उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास के एक नए मॉडल की ओर ले जा रही है, जहां गो पालन, जैविक खेती, स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता एक-दूसरे के पूरक बनकर गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी सशक्त आधार प्रदान करेगी।

वास्तव में, यह योजना गो संरक्षण को जनकल्याण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के साथ जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के विकास की एक प्रेरणादायक कहानी लिख रही है। ■



नए भारत की नई पहचान जनकल्याण से जनशक्ति तक

दुनिया का सबसे बड़ा कल्याणकारी अभियान, बदल रहा करोड़ों भारतीयों का जीवन

भारत आज केवल आर्थिक विकास की ओर अग्रसर राष्ट्र नहीं है, बल्कि जनकल्याण के क्षेत्र में भी विश्व के लिए एक प्रेरणास्रोत बनकर उभरा है। खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, वित्तीय समावेशन, बिजली और हर घर जल जैसी योजनाओं के माध्यम से देश करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है।

अन्न से आत्मविश्वास तक

भारतीय खाद्य निगमतथा विभिन्न सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे गरीब और वंचित वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

स्वच्छता से स्वास्थ्य की ओर

स्वच्छ भारत मिशन ने देशभर में स्वच्छता को जनआंदोलन का रूप दिया। लाखों शौचालयों के निर्माण से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और सम्मान दोनों को मजबूती मिली है।

स्वास्थ्य सुरक्षा का नया अध्याय

आयुष्मान भारत जैसी पहल ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच प्रदान की है। इससे स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का बोझ कम हुआ है और लाखों परिवारों को राहत मिली है।

हर परिवार का अपना आशियाना

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध हुए हैं। यह केवल मकान नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव है।

बैंकिंग सेवाएं पहुंचीं हर घर तक

प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। इससे सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है।

रोशनी से विकास का मार्ग

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत पहुंच के विस्तार ने शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। बिजली ने गांवों में विकास की नई संभावनाओं को जन्म दिया है।

हर घर जल: स्वस्थ जीवन की आधारशिला

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे महिलाओं का श्रम कम हुआ है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आई है।

समावेशी विकास का भारतीय मॉडल

भारत की विशेषता यह है कि यहां अनेक विशाल जनकल्याणकारी कार्यक्रम एक साथ संचालित हो रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। यह मॉडल "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" की भावना को साकार करता है। ■

जब विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। आज भारत जनकल्याण को जनशक्ति में बदलते हुए एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जहां अवसर, सम्मान और समृद्धि हर नागरिक का अधिकार बन रहे हैं।

विकसित भारत 2047 की दिशा में बिहार का आत्मविश्वासपूर्ण कदम

समावेशी मानव विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनता बिहार

नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद् की बैठक में बिहार ने अपने विकास के विजन, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य अब केवल विकास का सहभागी नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के निर्माण में एक अग्रणी शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बाल विकास और शिक्षा में नई ऊँचाइयाँ

बिहार ने बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हजारों आँगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं की स्थापना तथा बच्चों को APAAR ID से जोड़ने की पहल शिक्षा और पोषण के एकीकृत मॉडल को मजबूत कर रही है। विद्यालयों में इंटरनेट, स्मार्ट कक्षाओं और शत-प्रतिशत शौचालय सुविधा ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में नई संभावनाएँ खोली हैं।

कौशल विकास से आत्मनिर्भर युवा

पीएम-विश्वकर्मा योजना के तहत लाखों कारीगरों को प्रशिक्षण देकर बिहार ने कौशल आधारित अर्थव्यवस्था को गति दी है। पटना में स्थापित होने वाला आर्यभट्ट अंतर्राष्ट्रीय कौशल हब और आईटीआई सुदृढ़ीकरण की योजनाएँ युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करेंगी।

उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विस्तार

राज्य के सैकड़ों प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की स्थापना उच्च शिक्षा को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का प्रयास है। विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा के लिए IISER और School of Planning & Architecture जैसी संस्थाओं की स्थापना की माँग बिहार की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है।



"समृद्ध बिहार ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला है।"

खेलों का नया केंद्र बनता बिहार

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन ने बिहार को खेल मानचित्र पर नई पहचान दी है। आगामी वर्षों में राष्ट्रीय खेलों और विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी की तैयारी राज्य की बढ़ती खेल क्षमता का प्रमाण है।

कृषि और किसान सशक्तिकरण

एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करना तथा उद्यानिकी, मखाना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में संस्थागत विकास की पहल किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पर्यटन में वैश्विक पहचान की ओर

बोधगया, राजगीर और नालंदा जैसे ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक स्थलों को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना बिहार को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिला सकती है।

महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय उदाहरण

लखपति दीदी योजना के तहत 48 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर बिहार ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि महिला नेतृत्व आधारित ग्रामीण विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है।

ऊर्जा और हरित विकास में अग्रणी

सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और ताप विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से बिहार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रूफटॉप सोलर मिशन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता हरित विकास के संकल्प को मजबूत करती है।

उद्योग, निवेश और नई अर्थव्यवस्था

सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली नई नीतियों ने बिहार को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाया है। पिछले दो वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निजी निवेश ने राज्य की आर्थिक संभावनाओं को नई गति दी है।

ज्ञान और विरासत का संरक्षण

आठ लाख से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल युग से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल है, जिससे ज्ञान भारतम् मिशन को भी नई मजबूती मिली है।

समृद्ध बिहार, विकसित भारत

मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विकास दृष्टि यह दर्शाती है कि बिहार सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति, तकनीकी नवाचार और मानव विकास के संतुलित मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। राज्य का यह संकल्प केवल बिहार के विकास तक सीमित नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ■

जन औषधि: सस्ती दवाइयों से स्वस्थ भारत की नई पहचान



भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी पहल बनकर उभरी है। आज देशभर में **19,000 से अधिक जन औषधि केंद्र** संचालित हो रहे हैं, जो आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ ब्रांडेड दवाओं की तुलना में **50 से 90 प्रतिशत तक कम कीमत** पर उपलब्ध करा रहे हैं।

जन औषधि केंद्रों ने विशेष रूप से गरीब, मध्यमवर्गीय और ग्रामीण परिवारों के लिए चिकित्सा खर्च का बोझ कम करने में अहम भूमिका निभाई है। अब मरीजों को आवश्यक दवाइयों के लिए अधिक धन खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे उनकी बचत बढ़ी है और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है।

यह पहल केवल सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि "**स्वस्थ भारत – समृद्ध भारत**" के लक्ष्य को भी मजबूत कर रही है। गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को नई गति मिली है।

जन औषधि केंद्र आज लाखों परिवारों के लिए राहत का माध्यम बन चुके हैं। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि जब स्वास्थ्य सेवाएं किफायती और सुलभ होती हैं, तब समाज का हर वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है।

"जन औषधि केंद्र: हर घर की सेहत, हर परिवार की बचत"



बिहार का नवनिर्माण: विकसित भारत की मजबूत आधारशिला

सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विकास, निवेश और नई संभावनाओं की ओर बढ़ता बिहार



सैयद मोहम्मद अली

भारत के विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प में बिहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही संदेश बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली के होटल द अशोक में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार की तीव्र प्रगति के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। यह विचार केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि बिहार के बदलते स्वरूप और उसकी बढ़ती संभावनाओं का प्रतिबिंब है।

पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने आधारभूत संरचना, बिजली, सड़क संपर्क, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आज राज्य में बेहतर सड़कें, सुदृढ़ कनेक्टिविटी और विकासोन्मुखी योजनाएं आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बिहार में हो रहे बदलाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं और राज्य एक नई पहचान गढ़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम में उपस्थित नीति-निर्माताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने बिहार के विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। सभी ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि शिक्षा, पर्यटन, प्रशासनिक दक्षता, कानून-व्यवस्था और निवेश-अनुकूल वातावरण को और मजबूत बनाकर बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जा सकता है।

नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने बिहार को "असीम संभावनाओं वाला राज्य" बताते हुए कहा कि प्रभावी नीतियों और बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से संभावनाओं को उपलब्धियों में बदला जा सकता है। उन्होंने सामाजिक विकास के क्षेत्र में हुए सुधारों, विशेषकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धियों की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि बिहार तेज़ विकास की नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय तथा निवेश को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र को बिहार की नई पहचान बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से समृद्ध बिहार देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बिहार सरकार की विकासोन्मुखी सोच और पहल की सराहना की। साथ ही, राज्य के समग्र विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त एवं निवेश आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन सरकार, उद्योग जगत और नीति-निर्माताओं के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इससे राज्य में निवेश, उद्योग, पर्यटन और सामाजिक विकास के नए अवसरों का सृजन होता है।

बदलते बिहार की यह विकास यात्रा आने वाले वर्षों में देश के लिए प्रेरणा और प्रगति का नया मॉडल बन सकती है।

आज बिहार केवल परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे धरातल पर साकार भी कर रहा है। विकास, सुशासन और जनभागीदारी के बल पर राज्य एक नए युग की ओर अग्रसर है। यह नवनिर्माण केवल बिहार की प्रगति का प्रतीक नहीं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ■

भारत की स्वच्छ ऊर्जा शक्ति का वैश्विक प्रदर्शन

म्यांमार राष्ट्रपति का एनटीपीसी नेट्रा दौरा बना ऊर्जा सहयोग का नया अध्याय

ग्रेटर नोएडा स्थित एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस (NETRA) में म्यांमार के माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्री मिन आंग ह्लाइंग का दौरा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह भारत की उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व क्षमता और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में उसकी बढ़ती भूमिका का सशक्त प्रदर्शन भी था।

एनटीपीसी की अनुसंधान एवं विकास इकाई नेट्रा आज देश में ऊर्जा नवाचार का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। म्यांमार के राष्ट्रपति और उनके उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने यहां पहुंचकर उन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का अवलोकन किया, जो भविष्य की टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था की आधारशिला मानी जा रही हैं।

दौरे के दौरान एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह तथा नेट्रा के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक एवं प्रमुख श्री शाश्वत्तम ने प्रतिनिधिमंडल को एनटीपीसी की विकास यात्रा, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान तथा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को गति देने वाली पहलों की विस्तृत जानकारी दी।

नेट्रा परिसर में स्थापित 4 मेगावाट/1 मेगावाट-घंटा सौर माइक्रोग्रिड, 3 मेगावाट-घंटा वैनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन हब तथा कृषि एवं नगर ठोस अपशिष्ट आधारित गैसीकरण-से-विद्युत संयंत्र ने प्रतिनिधिमंडल को विशेष रूप से आकर्षित किया। ये सभी परियोजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि भारत केवल ऊर्जा उत्पादन में ही नहीं, बल्कि स्वच्छ, हरित और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

महामहिम राष्ट्रपति ने विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी तकनीकों में गहरी रुचि दिखाई। यह भारत की उन उपलब्धियों की अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, जो ऊर्जा क्षेत्र को पर्यावरण-अनुकूल और भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं।

यह दौरा भारत और म्यांमार के बीच ऊर्जा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्षमता निर्माण, तकनीकी आदान-प्रदान, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के विकास जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाएं दिखाई दीं।

आज जब विश्व स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब एनटीपीसी नेट्रा जैसे संस्थान भारत को वैश्विक ऊर्जा नवाचार मानचित्र पर नई पहचान दिला रहे हैं। म्यांमार राष्ट्रपति का यह दौरा न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का सम्मान है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विकसित और हरित भविष्य के निर्माण में भारत विश्व समुदाय का एक विश्वसनीय साझेदार बनकर उभर रहा है।

भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में यह दौरा एक ऐसी उपलब्धि है, जिसने अनुसंधान, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से टिकाऊ विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश दिया है। ■



पीएम स्वनिधि

सड़क किनारे आजीविका से आत्मनिर्भरता तक – एक ऐतिहासिक माइक्रो-क्रेडिट क्रांति



भारत के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों रेहड़ी-पटरी और ठेला विक्रेताओं के लिए PM SVANidhi योजना एक परिवर्तनकारी पहल सिद्ध हुई है। वर्ष 2020 में प्रारम्भ की गई यह योजना देश की पहली ऐसी माइक्रो-क्रेडिट पहल है, जो विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार समर्थित क्रेडिट गारंटी के साथ सुलभ ऋण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

आजीविका को मिला नया संबल

कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावित वर्गों में स्ट्रीट वेंडर्स भी शामिल थे। उनकी आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई थीं और औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था तक उनकी पहुँच सीमित थी। ऐसे समय में पीएम स्वनिधि योजना ने बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें अपने व्यवसाय को पुनः स्थापित करने का अवसर दिया।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण।
- समय पर भुगतान करने पर ब्याज में सब्सिडी।
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा और कैशबैक प्रोत्साहन।
- नियमित पुनर्भुगतान पर अधिक राशि के अगले ऋण की सुविधा।
- वित्तीय समावेशन और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ाव।

आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव

यह योजना केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम भी बनी है। लाखों विक्रेताओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर उनकी क्रेडिट हिस्ट्री विकसित की गई है, जिससे भविष्य में अन्य वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच आसान हुई है।

डिजिटल भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

पीएम स्वनिधि के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला है। इससे न केवल विक्रेताओं की आय में पारदर्शिता आई है, बल्कि ग्राहकों के लिए भी लेन-देन अधिक सुविधाजनक हुआ है। डिजिटल सशक्तिकरण के इस मॉडल ने छोटे व्यापारियों को आधुनिक अर्थव्यवस्था का सक्रिय भागीदार बनाया है।

सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का माध्यम

स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यह योजना उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती, बल्कि उनके श्रम और योगदान को औपचारिक मान्यता भी प्रदान करती है। इससे उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हुई है।

पीएम स्वनिधि योजना भारत में समावेशी विकास और वित्तीय सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। सरकार समर्थित क्रेडिट गारंटी, डिजिटल प्रोत्साहन और आसान ऋण सुविधा के माध्यम से इस योजना ने लाखों स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। यह पहल न केवल छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि भारत की शहरी अर्थव्यवस्था को भी अधिक सुदृढ़ और समावेशी बना रही है। ■

"पीएम स्वनिधि केवल एक ऋण योजना नहीं, बल्कि लाखों मेहनतकश स्ट्रीट वेंडर्स के सपनों को नई उड़ान देने का सशक्त माध्यम है।"

'गो ग्लोबल' हरियाणा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों के लिए खुले वैश्विक अवसरों के द्वार

हरियाणा आज कृषि क्षेत्र में एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित रखने के बजाय उन्हें वैश्विक बाजारों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एमडीएच और हरियाणा के छह किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के बीच हुआ समझौता राज्य के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। अब हरियाणा के किसान तंजानिया, केन्या सहित विभिन्न अफ्रीकी देशों में खेती और कृषि व्यवसाय के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। यह केवल एक समझौता नहीं, बल्कि हरियाणा के किसानों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का माध्यम है।

मोरनी क्षेत्र में अदरक, हल्दी, मिर्च और अन्य मसाला फसलों की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का निर्णय किसानों के लिए आय के नए स्रोत खोलेगा। सरकार ने प्रारंभिक चरण में लगभग 4 हजार एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती शुरू करने की योजना बनाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को प्राकृतिक खेती में किसी प्रकार का नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जाएगी तथा बाजार मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक मूल्य देने की व्यवस्था भी की गई है। यह किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



एमडीएच जैसी प्रतिष्ठित कंपनी किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, विपणन और खरीद की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इससे किसानों को अपनी उपज के लिए सुनिश्चित बाजार मिलेगा तथा बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, कीटनाशक-मुक्त और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलने से हरियाणा की कृषि अधिक पर्यावरण-अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक बनेगी।

इस पहल का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि हरियाणा के किसान पहली बार देश की सीमाओं से बाहर जाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि गतिविधियों से जुड़ सकेंगे। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि राज्य के कृषि निर्यात को भी नई गति मिलेगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हरियाणा की भागीदारी बढ़ने से राज्य कृषि व्यापार के अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की 'गो ग्लोबल' सोच हरियाणा के किसानों के लिए नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई संभावनाओं का संदेश लेकर आई है। यह पहल कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलने, युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निश्चित रूप से यह कदम हरियाणा को "वैश्विक कृषि शक्ति" के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक और दूरगामी प्रयास होगा। ■

विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की दमदार भागीदारी : 2047 तक 1 ट्रिलियन डॉलर योगदान का लक्ष्य

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के विकास, औद्योगिक विस्तार, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन से जुड़े दूरदर्शी प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा ने 'विजन-2047' के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का रोडमैप तैयार किया है। राज्य का लक्ष्य वर्ष 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देना तथा प्रति व्यक्ति आय को 40 लाख रुपये से अधिक तक पहुंचाना है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और समृद्ध हरियाणा की परिकल्पना को भी साकार करता है।

औद्योगिक विकास को नई गति

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की कि महत्वाकांक्षी औद्योगिक पार्क योजना के प्रथम 50 पार्कों में हरियाणा को भी शामिल किया जाए। साथ ही हरियाणा को सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जाए।

उन्होंने राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब विकसित करने तथा ग्रीन हाइड्रोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मांग रखी। ये पहल हरियाणा को भविष्य की तकनीकी और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।



शिक्षा में हरियाणा बना अग्रदूत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बनकर हरियाणा ने शिक्षा सुधारों में नेतृत्व का परिचय दिया है। राज्य में 17,859 स्कूल रेडीनेस मेलों के माध्यम से लाखों बच्चों और अभिभावकों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया गया।

'सुपर-100' योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में 267 विद्यार्थियों ने आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु 250 पीएम श्री स्कूल, 218 मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 250 सीएम ईई स्कूल स्थापित किए गए हैं। बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज उपलब्ध कराने की पहल भी सराहनीय है।

कौशल विकास और रोजगार में राष्ट्रीय नेतृत्व

राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। प्रति लाख जनसंख्या पर 1,520 युवा अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। इस उपलब्धि के लिए राज्य को 'चैंपियन ऑफ चेंज' सम्मान प्राप्त हुआ है।

ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग योजना के माध्यम से आईटीआई शिक्षा को उद्योगों से जोड़ा गया है, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 70 प्रतिशत से अधिक युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पीएम सेतू योजना के तहत स्थापित कौशल विकास क्लस्टर युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित कर रहे हैं।

खेलों का पावर हाउस बनता हरियाणा

खेल प्रतिभाओं को निखारने में हरियाणा की पहचान लगातार मजबूत हो रही है। एशियन गेम्स-2026 के लिए चयनित भारतीय कुश्ती टीम के सभी 18 खिलाड़ी हरियाणा से होना राज्य की खेल संस्कृति और प्रशिक्षण व्यवस्था की सफलता का प्रमाण है। मिशन ओलंपिक-2036 के अंतर्गत तैयार की गई 'विजयी भव' योजना युवा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार कर रही है। यह पहल हरियाणा को खेल क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

निवेश और रोजगार का नया अध्याय

'मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026' और नौ नई सेक्टोरल नीतियों के माध्यम से राज्य ने औद्योगिक निवेश को नई दिशा दी है। अगले पांच वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 10 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई नीतियों के लॉन्च के पहले ही दिन 1.10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना निवेशकों के बढ़ते विश्वास का स्पष्ट संकेत है। इनमें 30 हजार करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) परियोजनाएं शामिल हैं।

नीति आयोग की बैठक में हरियाणा द्वारा प्रस्तुत विकास दृष्टि यह दर्शाती है कि राज्य केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं, बल्कि शिक्षा, कौशल, तकनीक, उद्योग और खेलों के माध्यम से समग्र विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प में हरियाणा की यह सक्रिय भागीदारी भविष्य के सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव तैयार कर रही है। ■

"दूरदर्शी नेतृत्व, युवा शक्ति, तकनीकी नवाचार और औद्योगिक विकास के समन्वय से हरियाणा विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है।"

गांवों की नई पहचान
ग्राम सचिवालयों से सशक्त हो रहा ग्रामीण उत्तर प्रदेश

आत्मनिर्भर गांवों की मजबूत नींव

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास की तस्वीर तेजी से बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गांव अब केवल विकास योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि सुशासन और डिजिटल परिवर्तन के सक्रिय केंद्र बनते जा रहे हैं। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार बना है प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों का व्यापक नेटवर्क।

ग्राम सचिवालयों की स्थापना ने ग्रामीण प्रशासन को नई दिशा दी है। अब ग्रामीणों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन योजनाओं की जानकारी, मनरेगा सेवाएं, जन्म-मृत्यु पंजीकरण तथा अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए दूर-दराज के तहसील और ब्लॉक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। सरकारी सेवाएं गांव के द्वार तक पहुंचने से समय, श्रम और धन की बचत हो रही है, जिससे आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

इस परिवर्तन को और मजबूत बनाने के लिए पिछले पांच वर्षों में 24,311 आधुनिक पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। ये भवन केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण विकास के बहुआयामी केंद्र बनकर उभरे हैं। यहां पंचायत बैठकों, जनसुनवाई, डिजिटल सेवाओं और विकास योजनाओं की निगरानी के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

प्रदेश सरकार ने ग्राम सचिवालयों को तकनीकी रूप से भी सशक्त बनाया है। कम्प्यूटर, इंटरनेट, फर्नीचर, पेयजल और स्वच्छता जैसी सुविधाओं से युक्त इन सचिवालयों में पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती की गई है। इससे प्रशासनिक कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है।



पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जियो-फेन्स्ड एवं क्यूआर कोड तकनीक आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। ग्राम पंचायतों को मिलने वाली धनराशि के उपयोग की निगरानी डिजिटल माध्यमों से की जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अनुश्रवण प्रणाली व्यय की सतत समीक्षा कर रही है, जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता और वित्तीय पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय कॉल सेंटर और ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं ने प्रशासनिक दक्षता को नई ऊंचाई प्रदान की है। समस्याओं का त्वरित समाधान और बेहतर संवाद व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन को अधिक प्रभावी बना रही है। आज ग्राम सचिवालय और पंचायत भवन उत्तर प्रदेश के गांवों में सुशासन, डिजिटल सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन चुके हैं। यह पहल न केवल सरकारी योजनाओं की पहुंच को आसान बना रही है, बल्कि ग्रामीण समाज में विश्वास, पारदर्शिता और सहभागिता की भावना को भी मजबूत कर रही है।

उत्तर प्रदेश का यह मॉडल दर्शाता है कि जब विकास की योजनाएं तकनीक, पारदर्शिता और जनसुविधा के साथ जुड़ती हैं, तो गांवों का समग्र विकास संभव होता है। ग्राम सचिवालयों का यह सशक्त नेटवर्क वास्तव में "आत्मनिर्भर गांव, सशक्त उत्तर प्रदेश" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ■

विशेष

ग्रेटर नोएडा: स्मार्ट औद्योगिक विकास का उभरता राष्ट्रीय मॉडल

जब विकास बनता है अध्ययन का विषय

ग्रेटर नोएडा आज केवल एक औद्योगिक शहर नहीं, बल्कि भारत के नियोजित शहरी एवं औद्योगिक विकास का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है। यही कारण है कि भारत सरकार में सहायक सचिव के रूप में कार्यरत छह आईएएस अधिकारियों ने यहां की प्रमुख विकास परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए ग्रेटर नोएडा का दौरा किया। यह दौरा इस बात का प्रमाण है कि ग्रेटर नोएडा की विकास यात्रा अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है।

रोजगार और निवेश का सशक्त केंद्र

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप (IITGNL) ने उद्योग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 30 से अधिक बड़ी कंपनियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिनमें कई प्रतिष्ठित उद्योग उत्पादन शुरू कर चुके हैं। लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 23 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों ने इस क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की नई पहचान

आईआईटीजीएनएल टाउनशिप आधुनिक शहरी सुविधाओं का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑटोमेटिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम, 24 घंटे निर्बाध बिजली-पानी की व्यवस्था और उन्नत सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं इसे एक विश्वस्तरीय औद्योगिक नगर के रूप में स्थापित करती हैं। यह मॉडल भविष्य के स्मार्ट शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है।

ग्रेटर नोएडा की विकास गाथा यह संदेश देती है कि सुनियोजित नीतियां, आधुनिक आधारभूत संरचना और जनहित केंद्रित दृष्टिकोण किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय पहचान दिला सकते हैं। आईएएस अधिकारियों का यह अध्ययन दौरा न केवल ग्रेटर नोएडा की उपलब्धियों की पुष्टि करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यह शहर भारत के विकसित और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है।

मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी से विकास को गति

मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब (MMLH) जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी को नई दिशा देने वाली हैं। रेल, मेट्रो और बस सेवाओं का एकीकृत विकास न केवल परिवहन को सुगम बनाएगा, बल्कि व्यापार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

प्रशासनिक नेतृत्व और दूरदर्शी सोच

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के संबंध में साझा किए गए अनुभव प्रशासनिक दक्षता और दूरदर्शी सोच को दर्शाते हैं। किसानों, उद्योगों और युवाओं के हितों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास को गति देना इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है। ■



भारत-म्यांमार संबंधों को नई ऊँचाई

बोधगया से शुरू हुई विश्वास, संस्कृति और विकास की नई यात्रा

भारत और म्यांमार के संबंधों को हाल ही में एक नई ऊर्जा और दिशा मिली, जब म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग ने अपने प्रथम विदेशी दौरे के लिए भारत को चुना। यह केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों का सशक्त प्रतीक है।

इस यात्रा का सबसे प्रेरणादायक पहलू यह रहा कि राष्ट्रपति ने अपने दौरे की शुरुआत पवित्र बोधगया से की। भगवान बुद्ध की तपोभूमि से यात्रा प्रारंभ करना भारत और म्यांमार के साझा बौद्ध विरासत एवं आध्यात्मिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने का संदेश देता है।

व्यापार और विकास के नए अवसर

भारत और म्यांमार के बीच हुई वार्ता में व्यापार, दुर्लभ खनिज (Rare Earths), स्वास्थ्य सेवाओं, कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्राप्त होगी।

'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीति को मजबूती

म्यांमार भारत की 'Neighbourhood First', 'Act East' तथा इंडो-पैसिफिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। यह



सहयोग पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक सेतु को और मजबूत करेगा। बेहतर सड़क, रेल और समुद्री संपर्क क्षेत्रीय व्यापार और लोगों के बीच संवाद को बढ़ावा देंगे।

म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सांस्कृतिक विरासत, आपसी विश्वास और साझा विकास की भावना दोनों देशों को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है। यह भारत की वैश्विक भूमिका और पड़ोसी देशों के साथ उसके मजबूत होते संबंधों का एक सकारात्मक एवं प्रेरणादायक उदाहरण है।

सुरक्षा और तकनीकी सहयोग का विस्तार

दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा अन्य उभरती चुनौतियों पर मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया है। यह सहयोग क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

साझा विरासत, साझा भविष्य

भारत और म्यांमार के संबंध केवल पड़ोसी देशों के नहीं, बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच विश्वास, सहयोग और विकास की नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। आने वाले समय में यह साझेदारी न केवल द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाएगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सतत विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। ■

हरित क्रांति से आगे: अब बागवानी एवं एग्री-बिजनेस क्रांति का नेतृत्व करेगा हरियाणा

किसानों की समृद्धि, तकनीक की शक्ति और हरित भविष्य की नई उड़ान

हरियाणा ने एक बार फिर कृषि विकास के क्षेत्र में देश को नई दिशा दिखाने की पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 2,738 करोड़ रुपये की लागत से सतत बागवानी संवर्धन परियोजना तथा हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर के शुभारंभ ने प्रदेश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने की मजबूत नींव रखी है।

बागवानी बनेगी किसानों की आय का नया आधार

जलवायु परिवर्तन, गिरते भूजल स्तर और बढ़ती कृषि लागत जैसी चुनौतियों के बीच हरियाणा सरकार ने बागवानी को कृषि विकास का नया इंजन बनाने का संकल्प लिया है। फल, सब्जियां, मसाले, फूल, औषधीय पौधे, मशरूम और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में किसानों को आय बढ़ाने के व्यापक अवसर मिलेंगे।

परियोजना के अंतर्गत 400 बागवानी क्लस्टर, 500 उत्पादक समूह, 402 पैक हाउस, 4 लीड पैक हाउस, 3 फुलफिलमेंट सेंटर तथा 44 रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों की उपज सीधे बेहतर बाजारों तक पहुंच सकेगी।

> "आधुनिक तकनीक, मजबूत बाजार व्यवस्था और पर्यावरणीय संतुलन के साथ हरियाणा का कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरता और समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। यह पहल किसानों के सुनहरे भविष्य की मजबूत आधारशिला साबित होगी।"



खेत से बाजार तक मजबूत होगी वैल्यू चेन

वर्तमान में फलों और सब्जियों का बड़ा हिस्सा बाजार तक पहुंचने से पहले खराब हो जाता है। आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क और वैज्ञानिक भंडारण व्यवस्था इस नुकसान को कम करेगी। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और कृषि लाभकारी व्यवसाय के रूप में उभरेगी।

कृषि में तकनीक का नया युग

यह परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, डिजिटल कृषि सलाह, डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट सेंसर, इंटरनेट ऑफ प्लांट्स और ई-मार्केटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को खेतों तक पहुंचाएगी। इससे खेती अधिक वैज्ञानिक, उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनेगी।

विश्वस्तरीय अनुसंधान का लाभ किसानों तक

Kochi University और Maharana Pratap Horticultural University के बीच ज्ञान एवं अनुसंधान सहयोग से हरियाणा के किसानों को विश्वस्तरीय तकनीकी सहायता और नवीन कृषि नवाचारों का लाभ मिलेगा।

जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

विश्व पर्यावरण दिवस पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही 1,000 हेक्टेयर जलभराव प्रभावित भूमि पर बायोड्रेनेज तकनीक के माध्यम से पौधारोपण तथा शिवालिक एवं अरावली क्षेत्रों में नए जल भंडारण बांधों के निर्माण की योजना जल संरक्षण को नई मजबूती प्रदान करेगी।

युवा बनेंगे जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर

सरकार युवाओं को एग्री-बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, कृषि निर्यात और स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार सृजन की ओर प्रेरित कर रही है। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी गति देगी।

महिला सशक्तिकरण का नया अवसर

मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

हरियाणा की यह महत्वाकांक्षी पहल केवल कृषि परियोजना नहीं, बल्कि किसानों की समृद्धि, युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का समग्र विकास मॉडल है। जिस प्रकार हरियाणा ने देश को हरित क्रांति का मार्ग दिखाया था, उसी प्रकार अब बागवानी एवं एग्री-बिजनेस क्रांति के माध्यम से कृषि विकास का नया अध्याय लिखने की ओर अग्रसर है। ■

खनिज संपदा से नॉलेज इकोनॉमी तक विकसित झारखंड की नई उड़ान

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रखा समग्र विकास का दूरदर्शी विजन



नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के विकास का एक व्यापक और भविष्यदृष्टा रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड केवल खनिज संपदा का भंडार नहीं, बल्कि मानव संसाधन, नवाचार, कौशल और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का उभरता हुआ केंद्र बनने की क्षमता रखता है।

मुख्यमंत्री ने झारखंड को देश के अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि राज्य की खनिज संपदा का वास्तविक लाभ तभी संभव है, जब उसका मूल्य संवर्धन (Value Addition) राज्य के भीतर हो तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार और अवसर प्राप्त हों।

शिक्षा, कौशल और रोजगार : विकास की मजबूत नींव

राज्य सरकार शिक्षा और कौशल विकास को परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हुए तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विद्यार्थियों का चयन अब IIT और मेडिकल संस्थानों में होने लगा है। राज्य में 5000 उत्कृष्ट विद्यालय विकसित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है।

सारथी योजना के माध्यम से 6.76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), ड्रोन और सोलर टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित कर झारखंड नई अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रहा है।

महिला सशक्तिकरण की नई कहानी

राज्य की 53 हजार से अधिक महिलाओं को आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि राज्य की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही है।

स्वास्थ्य और पोषण में उल्लेखनीय प्रगति

झारखंड ने सीमित संसाधनों के बावजूद स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पोषण अभियान और SAAMAR जैसी योजनाओं के माध्यम से कुपोषण में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। बच्चों को नियमित रूप से अंडा उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 5000 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 1276 दवा दुकानों ने स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कृषि बना पोषण और समृद्धि का आधार

झारखंड में 10 लाख से अधिक पोषण वाटिकाओं का विकास और 1.5 लाख एकड़ भूमि पर फलदार पौधारोपण राज्य की कृषि क्रांति का परिचायक है। राज्य का आम अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहा है, जो किसानों की बढ़ती आय और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण है।

डिजिटल झारखंड की ओर बढ़ते कदम

राज्य सरकार AI आधारित CM Data Intelligence Platform और Integrated Command & Control Center विकसित कर रही है। डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली के माध्यम से प्रशासन को अधिक प्रभावी और जनोन्मुख बनाया जा रहा है।

खेल प्रतिभाओं को मिलेगा वैश्विक मंच

हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स में झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मांग रखते हुए झारखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी का अवसर देने का आग्रह किया।

उद्योग, नवाचार और हरित विकास का नया अध्याय

मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और एग्रो-फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों में बड़े निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही AI आधारित खनिज अन्वेषण और सतत खनन (Sustainable Mining) को भविष्य की औद्योगिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। ■

"झारखंड की नई पहचान — खनिज से मैन्युफैक्चरिंग, कौशल से समृद्धि और नवाचार से विकास"

आत्मनिर्भर गांवों की ओर बढ़ते कदम

टिहरी में आजीविका मॉडल बना विकास की नई पहचान

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण की नई कहानी लिखी जा रही है। जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड चम्बा में मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन का स्थलीय निरीक्षण केवल योजनाओं की समीक्षा भर नहीं था, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के सफल प्रयासों का प्रत्यक्ष अवलोकन भी था।

रीप (ग्रामोत्थान) परियोजना, स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी तथा स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। ग्राम दिखोलगांव में संचालित "हिमालयन भोजनालय" फूड कार्ट इस परिवर्तन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां महिलाओं ने स्थानीय व्यंजनों को रोजगार और सम्मानजनक आय का माध्यम बना दिया है। यह पहल दर्शाती है कि यदि अवसर और मार्गदर्शन मिले तो ग्रामीण महिलाएं आर्थिक विकास की अग्रणी शक्ति बन सकती हैं।

नागणी में निर्माणाधीन मिनी फिश प्रोसेसिंग यूनिट स्थानीय मत्स्य उत्पादन को मूल्य संवर्धन से जोड़कर किसानों और मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। यह परियोजना ग्रामीण उद्यमिता को नई पहचान देने के साथ-साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित करेगी।

भिन्नू ग्राम का पोल्ट्री फार्म यह प्रमाणित करता है कि पशुपालन आधारित स्वरोजगार मॉडल ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए स्थायी आय का प्रभावी साधन बन सकता है।



यह केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि ग्रामीण उत्तराखण्ड में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और समृद्धि की नई इबारत लिखने का अभियान है।



वहीं दुवाधार स्थित 3 हजार जैविक आउटलेट स्थानीय जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराकर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत कर रहा है।

मुख्य सचिव द्वारा गुणवत्ता, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार विस्तार पर दिया गया विशेष जोर इस बात का संकेत है कि अब ग्रामीण उत्पादों को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें व्यापक बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादों की पहचान मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी आधार मिलेगा।

टिहरी गढ़वाल में संचालित ये पहलें इस बात का प्रमाण हैं कि सरकारी योजनाएं, स्वयं सहायता समूहों की प्रतिबद्धता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी मिलकर विकास का ऐसा मॉडल तैयार कर सकती हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को जमीनी स्तर पर साकार कर रहा है। ■



महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

पूर्वांचल की कृषि क्रांति का नया अध्याय

उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा में कुशीनगर एक नई पहचान के साथ उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्माणाधीन **महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय** का निरीक्षण और उसके शीघ्र संचालन की घोषणा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आशा और संभावनाओं का नया संदेश लेकर आई है। लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रहा यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और समृद्धि का केंद्र बनने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना, उत्पादन लागत को कम करना तथा फसल उत्पादकता बढ़ाकर उनकी आय में वृद्धि करना है। यह संस्थान कृषि अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश लंबे समय से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा है, लेकिन आधुनिक तकनीकी संसाधनों और अनुसंधान संस्थानों की कमी महसूस की जाती रही है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस कमी को दूर करते हुए क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इससे युवाओं को कृषि शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

कुशीनगर का बदलता स्वरूप भी इस परियोजना की सफलता को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। मेडिकल कॉलेज, बेहतर सड़क संपर्क, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा नए आर्थिक गलियारों के निर्माण ने जिले को विकास के नए मानचित्र पर स्थापित किया है। अब कृषि विश्वविद्यालय इस विकास यात्रा में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है।

यह विश्वविद्यालय केवल किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि पूर्वांचल में कृषि आधारित उद्योगों, स्टार्टअप्स और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करेगा। वैज्ञानिक खेती, जैविक कृषि, कृषि यंत्रीकरण और मूल्य संवर्धन जैसी आधुनिक अवधारणाओं को बढ़ावा देकर यह संस्थान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा।

निश्चित रूप से, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का नया सूर्योदय साबित होगा। यह परियोजना कृषि विकास, शिक्षा और क्षेत्रीय प्रगति के संगम के रूप में आने वाले वर्षों में पूर्वांचल की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। ■

सेवा, साधना और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल

समालखा से विकसित भारत की ओर एक प्रेरक पहल

भारत के विकास का वास्तविक आधार उसके गांव हैं। जब गांव मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनते हैं, तभी विकसित भारत का सपना साकार होता है। समालखा स्थित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र इसी सोच को धरातल पर उतारने का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है।

वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस केंद्र को केवल एक संस्था नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का जीवंत मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि आसपास के 100 गांवों के समग्र विकास का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहा यह केंद्र शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक उत्थान के क्षेत्रों में नई चेतना का संचार कर रहा है।

केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां सेवा, साधना और ग्राम विकास की त्रिवेणी एक साथ प्रवाहित होती दिखाई देती है। जहां एक ओर युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों को प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रेरित कर टिकाऊ कृषि व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाएं किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई हैं। देसी गाय पर बढ़ी हुई सब्सिडी, प्राकृतिक खेती हेतु आवश्यक संसाधनों के लिए आर्थिक सहायता तथा जैविक उत्पादों के बेहतर विपणन की व्यवस्था किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।



युवाओं के लिए स्थापित कौशल विकास केंद्र और खेल नर्सरी भविष्य के सशक्त भारत की नींव रख रहे हैं। यह पहल युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाला बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। वहीं खेलों के क्षेत्र में हरियाणा की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भी यह केंद्र नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर रहा है।

"आत्मनिर्भर गांव, सक्षम युवा और समृद्ध किसान ही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव हैं।"

समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए प्रस्तावित छात्रावास शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के नए द्वार खोलेंगे। यह अंत्योदय की भावना को साकार करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचेगा।

सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र आज यह संदेश दे रहा है कि जब समाज स्वयं अपने विकास का संकल्प लेता है, तो परिवर्तन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। यह केंद्र ग्राम विकास, सामाजिक सहभागिता और आत्मनिर्भरता का ऐसा मॉडल बन रहा है, जो भविष्य में पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हो सकता है। ■

कपास आयात पर शुल्क छूट

भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए विकास और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान

भारत का वस्त्र एवं परिधान उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर सभी सीमा शुल्क (Custom Duty) को अस्थायी रूप से समाप्त करने का सराहनीय निर्णय लिया है।



यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब वस्त्र उद्योग को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। शुल्क छूट के कारण कपास आयात की लागत कम होगी, जिससे सूत, कपड़ा और परिधान निर्माताओं को कच्चा माल अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेगा। इसका सीधा लाभ उत्पादन लागत में कमी के रूप में दिखाई देगा, जिससे उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और मजबूत होगी।



विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) इस निर्णय से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। सीमित संसाधनों के साथ कार्य करने वाले इन उद्यमों को सस्ती दरों पर कपास उपलब्ध होने से उत्पादन बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

सरकार का यह कदम केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखता है। उत्पादन लागत घटने से वस्त्र और परिधान उत्पादों की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आम उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे।

"सुलभ कपास, सशक्त उद्योग और समृद्ध भारत" — यही इस ऐतिहासिक निर्णय का सार है।"

साथ ही, यह निर्णय किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सीमित अवधि के लिए लागू किया गया है। इससे बाजार में कपास की उपलब्धता बनी रहेगी और उद्योग की मांग तथा किसानों के हितों के बीच संतुलन स्थापित होगा। यह नीति सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों के विकास को समान महत्व दिया गया है।

कुल मिलाकर, कपास आयात पर अस्थायी शुल्क छूट भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए एक सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम है। यह न केवल उद्योग की उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, बल्कि रोजगार, निर्यात और आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। आने वाले महीनों में यह पहल भारतीय वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत एवं प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ■

खेत बचाओ अभियान

जलवायु चुनौतियों के बीच सुरक्षित खेती और समृद्ध किसान की ओर बढ़ता उत्तराखंड

जनभागीदारी से जनआंदोलन बना कृषि संरक्षण का अभियान



उत्तराखंड की समृद्ध कृषि परंपरा, प्राकृतिक संसाधनों और किसानों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अल्मोड़ा के हवालबाग में आयोजित राज्य स्तरीय 'खेत बचाओ अभियान' कार्यक्रम ने एक नई ऊर्जा और सकारात्मक संदेश का संचार किया। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच यह अभियान केवल खेती बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि मिट्टी, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का संकल्प बनकर उभरा है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि खेत, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने इस अभियान को जनभागीदारी से जुड़ा जनआंदोलन बताते हुए किसानों से अपनी कृषि भूमि और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने का आह्वान किया।



किसान हैं विकास की असली ताकत

मुख्यमंत्री ने किसानों को देश की शक्ति और आत्मनिर्भर भारत की नींव बताते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। किसानों की आय वृद्धि के लिए बजट में



200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी।

उन्होंने किसानों को मिट्टी परीक्षण, जल संरक्षण और वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि बदलती जलवायु के अनुरूप फसलों का चयन करना भविष्य की आवश्यकता है। साथ ही मोटे अनाजों—मांडुआ, झंगोरा, चौलाई एवं अन्य पारंपरिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।

पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि का संतुलन

कार्यक्रम का प्रमुख संदेश था कि 'इकोलॉजी और इकोनॉमी' एक-दूसरे के पूरक हैं। स्वस्थ पर्यावरण ही समृद्ध अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं का विस्तार

राज्य सरकार द्वारा बागवानी, फलोत्पादन, पॉलीहाउस, कोल्ड स्टोरेज, मेगा फूड पार्क और सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढ़े हैं।

'खेत बचाओ अभियान' केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि उत्तराखंड की कृषि संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और किसान समृद्धि का व्यापक आंदोलन बनता जा रहा है। यह अभियान आने वाले समय में टिकाऊ खेती, सुरक्षित खेत और खुशहाल किसान के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

अल्मोड़ा को मिली बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद में खेती की सुरक्षा के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से तारबाड़ योजना लागू किए जाने की घोषणा की। इससे जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसानों का नुकसान कम होगा।

आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मिलेट जैसी फसलों को बढ़ावा देकर कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेतों का संरक्षण ही आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का आधार बनेगा।

संकल्प से सशक्त होगा भविष्य

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों, महिला समूहों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सहभागिता करते हुए कृषि संरक्षण, मिट्टी संवर्धन और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने का सामूहिक संकल्प लिया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित कर उनके प्रयासों को नई पहचान भी दी गई। ■



सुरक्षा का मजबूत कवच हर परिवार तक सामाजिक संरक्षण की पहुंच

भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है, जहां सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों तक समय रहते पहुंचकर उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबारने का कार्य कर रही हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM Suraksha Bima Yojana) एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभरी है।

इस योजना के माध्यम से देशभर में 58 करोड़ से अधिक नागरिकों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा का लाभ प्राप्त हुआ है। बेहद कम प्रीमियम पर उपलब्ध यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सुरक्षा का मजबूत कवच साबित हो रही है। दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाली वित्तीय सहायता परिवारों को अचानक आने वाले संकट से उबरने में मदद करती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केवल एक बीमा योजना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में विश्वास, सुरक्षा और सम्मान का आधार बन चुकी है। यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी परिवार को आकस्मिक दुर्घटना के बाद आर्थिक असुरक्षा का सामना अकेले न करना पड़े।

"सुरक्षित नागरिक, सशक्त परिवार और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम।"

सामाजिक संरक्षण की यह व्यापक पहुंच प्रधानमंत्री के उस संकल्प को साकार करती है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को

सुरक्षा और अवसर प्रदान कर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत का निर्माण किया जा रहा है। आज यह योजना

समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा का संदेश पहुंचाते हुए "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" की भावना को मजबूत कर रही है। ■



डिजिटल क्रांति से सशक्त हो रहा भारत

कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में नया अध्याय

भारत में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक सुविधाओं और आर्थिक सहायता को पहुंचाने की व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व बदलाव से गुजरी है। यह परिवर्तन किसी बड़े शोर-शराबे के बिना, एक "मौन क्रांति" के रूप में सामने आया है, जिसने सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण की परिभाषा ही बदल दी है।

आज डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों के बैंक खातों तक पहुंच रहा है। **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), आधार आधारित प्रमाणीकरण और जनधन खातों** के समन्वय ने कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है।

पहले लाभार्थियों को सहायता प्राप्त करने के लिए कई स्तरों की प्रक्रियाओं और बिचौलियों से गुजरना पड़ता था, जिससे समय की बर्बादी, भ्रष्टाचार और रिसाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इन चुनौतियों को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। अब सहायता राशि सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में पहुंचती है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हुआ है।

भारत की यह डिजिटल कल्याण क्रांति इस बात का प्रमाण है कि तकनीक जब जनहित के साथ जुड़ती है, तो शासन अधिक संवेदनशील, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बन जाता है।

कोविड-19 महामारी के दौरान इस डिजिटल व्यवस्था की उपयोगिता पूरे विश्व ने देखी। करोड़ों लोगों तक राहत राशि और अन्य सहायता समयबद्ध तरीके से पहुंचाई गई, जिससे संकट की घड़ी में सामाजिक सुरक्षा का मजबूत तंत्र स्थापित हुआ।

डिजिटल कल्याण प्रणाली ने महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के वंचित वर्गों को विशेष रूप से सशक्त बनाया है। लाभार्थी अब अपने अधिकारों और प्राप्त सुविधाओं की जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, जिससे शासन में विश्वास और सहभागिता दोनों बढ़ी हैं।

यह परिवर्तन केवल तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि "**अंत्योदय से आत्मनिर्भरता**" की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल इंडिया की यह पहल सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के नए मानक स्थापित कर रही है। ■

सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र

आत्मनिर्भर युवाओं के भविष्य की मजबूत नींव

उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में नई दिशा देने की महत्वाकांक्षी पहल के रूप में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र (SVBPEIZ) तेजी से आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने परियोजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसके निर्माण कार्यों को गति प्रदान की जाए तथा इसे केवल एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए।

यह परियोजना युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्योग स्थापित करने तक की संपूर्ण यात्रा के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगी। SVBPEIZ परिसर में कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले औद्योगिक सुविधाएं, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा उद्यमिता सहायता सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि युवाओं को अलग-अलग संस्थानों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशिक्षण, प्रमाणन, रोजगार अवसरों की जानकारी, उद्योगों से संपर्क और स्वरोजगार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एक ही परिसर में उपलब्ध होगा।

परियोजना के पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक जॉब मैचिंग और प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80 प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना इस पहल को और अधिक प्रभावी बनाती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भूमि उपलब्धता, संस्थागत ढांचे, निजी क्षेत्र की सहभागिता तथा क्रियान्वयन मॉडल से संबंधित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेकर परियोजना को निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाया जाए। यह पहल न केवल युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

SVBPEIZ वास्तव में एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जहां कौशल, रोजगार और उद्यमिता एक साथ मिलकर युवा शक्ति को सशक्त बनाएंगे और विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करेंगे। ■



विज्ञान से विकास की उड़ान: उत्तराखंड के नवाचार युग की शुरुआत

उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2026 बनेगी आत्मनिर्भर और विकसित राज्य की नई आधारशिला

उत्तराखंड ने विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार आधारित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए "उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2026" लागू कर दी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तैयार की गई यह नीति राज्य को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच के नए युग में प्रवेश कराने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

नई नीति केवल विज्ञान और तकनीक के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य विज्ञान को आम जनजीवन, सुशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और आपदा प्रबंधन से जोड़ना है। विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी समाधान विकसित करने पर बल दिया गया है।

नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, स्टार्टअप्स और जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों को एक साझा मंच प्रदान किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ड्रोन, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवाचार को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इससे राज्य के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे और रोजगार के आधुनिक विकल्प विकसित होंगे।

शिक्षा क्षेत्र में भी यह नीति दूरगामी प्रभाव डालेगी। अटल टिंकरिंग लैब, एआई प्रयोगशालाएं, विज्ञान केंद्र, तारामंडल और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना से विद्यार्थियों में



वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा अत्याधुनिक शिक्षण-अधिगम केंद्र शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

उत्तराखंड की समृद्ध पारंपरिक ज्ञान परंपरा को आधुनिक विज्ञान और अनुसंधान से जोड़ने का प्रयास इस नीति को विशेष बनाता है। इससे स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक अनुभवों का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित होगा तथा "आत्मनिर्भर उत्तराखंड" की अवधारणा को नई गति मिलेगी।

नीति के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली "विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार वेधशाला" राज्य में संचालित सभी योजनाओं, अनुदानों और नवाचार गतिविधियों का डिजिटल केंद्र बनेगी। वहीं वैज्ञानिक समुदाय के लिए विकसित किया जाने वाला विशेष सहभागिता पोर्टल शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच सहयोग और संवाद को मजबूत करेगा।

"विज्ञान से समृद्धि, नवाचार से आत्मनिर्भरता और तकनीक से विकसित उत्तराखंड की ओर एक सशक्त कदम।"

"नई नीति की 5 बड़ी उपलब्धियां"

- AI, ड्रोन, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों को बढ़ावा
- विज्ञान नगरी, तारामंडल और एआई लैब की स्थापना
- युवाओं, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर
- पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय
- आत्मनिर्भर एवं विकसित उत्तराखंड के निर्माण को नई गति

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि उत्तराखंड को केवल तकनीकी रूप से सक्षम ही नहीं, बल्कि नवाचार आधारित, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में विकसित किया जाए। महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों, सीमांत समुदायों और दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली यह नीति सामाजिक समावेशन का भी मजबूत संदेश देती है।

निस्संदेह, उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2026 राज्य को विज्ञान आधारित विकास, तकनीकी प्रगति और नवाचार संस्कृति की नई पहचान प्रदान करेगी। यह नीति आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। ■

विकसित भारत की दिशा में उत्तराखंड का दमदार विजन

नीति आयोग में गूंजा विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता का मंत्र

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के समग्र विकास का एक दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत कर राज्य की प्रगतिशील सोच और भविष्य की विकास यात्रा को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से रखा। मुख्यमंत्री ने "विकसित भारत-2047" के लक्ष्य को साकार करने में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए मानव संसाधन विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण को विकास का आधार बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण, विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना तथा कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देकर नई पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाया जा रहा है।

युवा शक्ति बनेगी विकास की सबसे बड़ी ताकत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं को दक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार अनेक अभिनव योजनाएं संचालित कर रही है। देवभूमि उद्यमिता विकास योजना, स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम तथा आईटीआई संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने जैसी पहलें उत्तराखंड को नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।



प्राकृतिक संसाधनों से सशक्त अर्थव्यवस्था की ओर

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती, बागवानी, औषधीय पौधों, योग एवं वेलनेस, पर्यटन और ग्रीन एनर्जी को भविष्य के विकास इंजन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, वेलनेस इकोनॉमी और सतत विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति समर्थन की मांग

देवभूमि उत्तराखंड की पर्यावरणीय और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण, आपदा प्रबंधन, कार्बन न्यूट्रैलिटी और पर्वतीय अवसंरचना विकास जैसे विषयों पर विशेष नीति समर्थन तथा दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमालय, गंगा, यमुना और विशाल वन क्षेत्र केवल उत्तराखंड की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं।

सुशासन और तकनीकी नवाचार की नई पहचान

राज्य में देवभूमि परिवार पहचान योजना, खनन क्षेत्र में डिजिटल निगरानी प्रणाली, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया का ऑनलाइन सरलीकरण तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े सुधारों ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनोन्मुखी बनाया है। वहीं पीरूल आधारित ऊर्जा उत्पादन जैसे नवाचार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय रोजगार सृजन का नया माध्यम बन रहे हैं।

उत्तराखंड से मिला आध्यात्मिक आमंत्रण

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके सफल 12 वर्षीय नेतृत्वकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए अगले वर्ष उत्तराखंड में आयोजित होने वाले भव्य कुंभ मेला एवं विश्व प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा में सहभागी बनने का आमंत्रण भी दिया।

उत्तराखंड आज विकास, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के समन्वय से एक नए युग की ओर अग्रसर है। "विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड" का संकल्प राज्य को राष्ट्रीय प्रगति के अग्रणी मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ■

"युवा शक्ति, नवाचार, हरित विकास और सुशासन के बल पर उत्तराखंड बना रहा है विकसित भारत का मजबूत आधार।"

छत्तीसगढ़ बनेगा आयुर्वेद और अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र को मिल सकती है नई दिशा



नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की महत्वपूर्ण मुलाकात ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) की स्थापना का प्रस्ताव रखकर छत्तीसगढ़ को आयुर्वेद चिकित्सा एवं अनुसंधान के राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने की दूरदर्शी पहल की है।

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक औषधीय संपदा, जैव विविधता और जनजातीय पारंपरिक ज्ञान की समृद्ध विरासत से परिपूर्ण है। ऐसे में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना न केवल प्रदेश के लाखों नागरिकों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, बल्कि युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा, शोध और नवाचार के नए अवसर भी सृजित करेगी।

नई दिल्ली और गोवा में स्थापित AIIA संस्थानों ने आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित संस्थान मध्य भारत के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य एवं अनुसंधान केंद्र बन सकता है। इससे प्रदेश में आयुर्वेद आधारित उपचार प्रणाली को मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा स्थानीय औषधीय वनस्पतियों पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय बजट 2026 में घोषित तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों में से एक संस्थान छत्तीसगढ़ को प्रदान करने का आग्रह किया है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा और 'विकसित छत्तीसगढ़' के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से भी केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया। श्री अमित शाह द्वारा राज्य के विकास प्रयासों की सराहना और हरसंभव सहयोग का आश्वासन केंद्र एवं राज्य के बीच मजबूत समन्वय का सकारात्मक संकेत है।

यह पहल केवल एक संस्थान की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला रखने वाला महत्वपूर्ण प्रयास है। ■

यमुना एक्सप्रेसवे पर उभर रहा भारत-कोरिया औद्योगिक सहयोग का नया अध्याय

कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने YEIDA में तलाशे निवेश के नए अवसर, 'कोरियन सिटी' बनेगी वैश्विक औद्योगिक साझेदारी का केंद्र

निर्माणशाला टाइम्स विशेष रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश का यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र अब वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इसी क्रम में 25 जून 2026 को दक्षिण कोरिया के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने **यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA)** का दौरा कर क्षेत्र में उपलब्ध निवेश संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन किया। यह यात्रा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

प्रतिनिधिमंडल में दक्षिण कोरिया के **व्यापार, उद्योग एवं संसाधन मंत्रालय, कोरिया दूतावास तथा कोरिया ट्रेड-इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी (KOTRA)** के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर YEIDA के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी **श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया (आईएएस)** ने क्षेत्र की औद्योगिक क्षमताओं, आधुनिक अवसंरचना और निवेश-अनुकूल वातावरण पर विस्तृत प्रस्तुति दी।



नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना निवेश आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र

श्री भाटिया ने बताया कि **नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट** के संचालन से यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र



वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना का समन्वय निवेशकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि क्षेत्र में **सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स तथा उभरते औद्योगिक क्षेत्रों** में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। इससे यहां का औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम और अधिक मजबूत हुआ है।

'कोरियन सिटी' : विदेशी निवेश और सांस्कृतिक समन्वय का नया मॉडल

प्रस्तुति का प्रमुख आकर्षण सेक्टर **4ए में प्रस्तावित 'कोरियन सिटी'** रही। लगभग **900 एकड़ क्षेत्र** में विकसित होने वाली यह परियोजना भारतीय औद्योगिक विकास के इतिहास में एक अनूठी पहल मानी जा रही है।

'मल्टीपल लैंड यूज इंडस्ट्री' अवधारणा पर आधारित इस परियोजना में औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ आवासीय, वाणिज्यिक एवं संस्थागत सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। इसका उद्देश्य कोरियाई कंपनियों और निवेशकों को एक ऐसा समग्र वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां वे व्यवसाय के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी सहज महसूस कर सकें।

वैश्विक कंपनियों की बढ़ती मौजूदगी से मजबूत हो रहा औद्योगिक विश्वास

YEIDA क्षेत्र में पहले से ही कई प्रतिष्ठित कंपनियों की उपस्थिति निवेशकों के विश्वास को मजबूत कर रही है। आधुनिक कनेक्टिविटी, निवेश-अनुकूल नीतियां और भविष्य उन्मुख योजनाएं इस क्षेत्र को देश के सबसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक हब के रूप में स्थापित कर रही हैं।

"यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र केवल एक औद्योगिक कॉरिडोर नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के आर्थिक विकास का प्रवेश द्वार बनता जा रहा है। कोरियाई प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है और 'कोरियन सिटी' जैसी पहलें भारत को विश्व स्तरीय औद्योगिक गंतव्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगी।"

स्थल निरीक्षण ने बढ़ाई निवेश संभावनाएं

प्रस्तुति के उपरांत कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने उन संभावित भूमि पार्सलों का भी निरीक्षण किया जिन्हें भविष्य में कोरियाई कंपनियों के निवेश हेतु चिन्हित किया गया है। इस दौरान प्रतिनिधियों ने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, अवसंरचना और औद्योगिक संभावनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।



उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति

विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा न केवल भारत–कोरिया आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक विनिर्माण एवं निवेश मानचित्र पर और अधिक सशक्त पहचान दिलाएगा। प्रस्तावित 'कोरियन सिटी' और बढ़ते विदेशी निवेश से रोजगार सृजन, तकनीकी हस्तांतरण तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। ■



स्वास्थ्य और कृषि विकास की नई दिशा

केंद्र-राज्य समन्वय से सशक्त होता छत्तीसगढ़

निर्माणशाला टाइम्स । विशेष लेख

छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बीच नई दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक ने स्वास्थ्य, कृषि और जनकल्याण के क्षेत्र में सकारात्मक संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं।

जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता, ग्रामीण अंचलों तक पहुंचेगी बेहतर चिकित्सा

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाएगी, बल्कि प्रदेश के नागरिकों को अपने ही राज्य में आधुनिक और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

किसानों के हित सर्वोपरि: खाद-बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित

खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। कालाबाजारी, जमाखोरी और वितरण में लापरवाही के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश सरकार की किसान-हितैषी सोच को दर्शाते हैं।

यह बैठक केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि जनहित, किसान कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास निश्चित रूप से राज्य को समावेशी और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। केंद्र और राज्य के बीच यही सहयोग "विकसित छत्तीसगढ़" और "विकसित भारत" के संकल्प को साकार करने का मजबूत आधार बनेगा।

आधुनिक कृषि की ओर बढ़ते कदम

छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चला रही है। नई तकनीकों को अपनाने से खेती की उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने और किसानों की आय में वृद्धि की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। यह प्रयास कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

नैनो उर्वरकों से कृषि में नवाचार

राज्य सरकार द्वारा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देना कृषि क्षेत्र में नवाचार की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इन उर्वरकों के उपयोग से खेती की लागत कम करने, मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। किसानों के बीच इसके लाभों को पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान भविष्य की टिकाऊ कृषि व्यवस्था का आधार बन सकते हैं।

केंद्र-राज्य सहयोग: विकास का मजबूत आधार

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश केंद्र और राज्य सरकार के बीच मजबूत समन्वय का रहा। स्वास्थ्य, कृषि और जनकल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों से विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का मार्ग और अधिक सुदृढ़ होगा। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रयासों की सराहना और हरसंभव सहयोग का आश्वासन राज्य के विकास के लिए सकारात्मक संकेत है। ■

IFFCO KISAN DRONE

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

इफको नैनो उर्वरक अपनाएं
अधिक उपज और गुणवत्ता पाएं
इफको की असरदार जोड़ी

नैनो यूरिया प्लस

नैनो डीएपी

नैनो जिंक

नैनो कॉपर



अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री न. 1800-103-1967

www.iffco.in | www.nanourea.in I www.nanodap.in

यूपी का विधाता अन्नदाता



21%
देश के खाद्यान्न उत्पादन में योगदान

नवनिर्माण के 9 वर्ष

खाद्यान्न, गन्ना, चीनी, आम दुग्ध, आलू उत्पादन में
1 देश में नंबर



3.12 करोड़ किसानों को
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
₹99 हजार करोड़+
की राशि अंतरित

रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान
₹3.15 लाख करोड़+
गन्ना मूल्य ₹315 से बढ़ाकर
₹400 प्रति क्विंटल

बिचौलिया मुक्त बाजार
ई-मंडी में 6.42 करोड़+ पर्चियां

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
3.53 करोड़+ किसानों
को क्षतिपूर्ति

किसानों को कार्बन क्रेडिट धनराशि वितरित करने वाला
प्रथम राज्य

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत
86 हजार+
सोलर पंपों की स्थापना

निःशुल्क बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी हेतु
'उत्तर प्रदेश मंडी भाव'
मोबाइल ऐप

86 लाख+
लघु/सीमांत किसानों का
फसल ऋण माफ

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश